'' राजनयिक परामर्श द्वारा समस्या समाधान : आयरलैण्ड शांति समझौता : एक विश्लेषण''

(एम. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध)

प्रीति चौधरी

राजनय, अंतर्राष्ट्रीय विधि एंव
आर्थिक अध्ययन केन्द्र,
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
1999

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI - 110067

राजनय, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं
आर्थिक अध्ययन केन्द्र,
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
ज.ने.वि.

दिनाँक 20/7/99

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रीति चौधरी द्वारा प्रस्तुत "**राजनयिक परामर्श द्वारा समस्या समाधान : आयरलैण्ड शांति समझौता : एक विश्लेषण**" शीर्षक लघु शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त सामग्री का इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में इससे पूर्व किसी प्रदेय उपाधि के लिए उपयोग नहीं किया गया है। यह लघु शोध प्रबन्ध प्रीति चौधरी की मौलिक कृति है।

प्रो. पुष्पेश पन्त
अध्यक्ष,
राजनय, अंतर्राष्ट्रीय विधि
एवं आर्थिक अध्ययन केन्द्र,
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
ज.ने.वि.

प्रो. पुष्पेश पन्त
शोध निर्देशक

1999

समर्पण

सोना, मनु, जूही, नेहा और तेजस के लिए

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	1 - 9
अध्याय प्रथम	10 - 30
उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास	
अध्याय द्वितीय	31 - 51
शांति समझौते की पृष्ठभूमि	
अध्याय तृतीय	52 - 82
शांति समझौता : एक विवेचना	
निष्कर्ष	83 - 90
संदर्भ सूची	91 - 100

आभार

इस लघु शोध प्रबन्ध के लेखन में, अपने शोध निर्देशक प्रो० पुष्पेश पंत से प्राप्त मार्गदर्शन व सहयोग के लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूं। समस्या व संघर्ष समाधान तथा परामर्श की सैद्धांतिक समझ विकसित करने में डा. विनायक के. राव की कक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध संबंधी अध्ययन सामग्री एकत्रित करने में डा० राव से मिले सहयोग के लिए मैं उनकी भी आभारी हूं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लेखन में अपनी मित्रों कार्तिका, शशिकुमार व अनुपम पाण्डेय से प्राप्त सुझावों के लिए संभवत: उन्हें औपचारिक धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। बी. एच. यू. व बलिया के मित्रों स्मिता, मनु, दीपा, ऐनी, रजनीश, चेतना व सौम्या का स्नेह मेरी पूंजी है। जे. एन. यू. में अर्पिता, चित्तरंजन, स्वाति, सीमा और विशेषकर प्रिय कुसुम से प्राप्त सहयोग के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

जीवन के प्रत्येक सफल-असफल मोड़ पर अपने परिवार से प्राप्त विश्वास तथा अपरिमित प्रेम ही मेरी शक्ति है और सहृदयी, सरलमना मित्र का साथ मेरा संबल, जिनके बिना कोई भी कार्य असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है।

अंत में मैं कम समय में कुशलता से टंकण कार्य संपादित कर कार्य को आसान बनाने के लिए श्री बी. पी. भाटिया को विशेष धन्यवाद देती हूं।

प्रीति चौधरी

प्राक्कथन

वर्ष 1998 के प्रतिष्ठित नोबल शांति पुरस्कार के लिए 130 नामांकन स्वयं में एक कीर्तिमान था, किन्तु यह संभावना भी निर्विवाद थी कि इस पुरस्कार के स्वाभाविक विजेता वे लोग ही होंगे, जिन्होंने उत्तरी आयरलैण्ड में शांति प्रस्थापित की । नोबल पुरस्कार समिति ने उत्तरी आयरलैण्ड के प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक समुदायों के अग्रणी नेताओं - डेविड ट्रिम्बल और जान ह्युम को पुरस्कृत करते हुए उनके व्यक्तिगत शांति प्रयत्नों की जिस प्रकार से भूरि-भूरि प्रशंसा की, उससे यह निश्चित रूप से प्रकट हुआ कि यह पुरस्कार मात्र व्यक्तिगत प्रयत्नों की सराहना भर नहीं था, अपितु यह इस सत्य की अभिव्यक्ति भी था कि दीर्घ काल से चले आ रहे जटिल रक्तरंजित संघर्ष का समाधान राजनयिक परामर्श व राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा अवश्य संभव है ।[1] 10 अप्रैल 1998 के शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैण्ड गणराज्य व उत्तरी आयरलैण्ड के सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के मध्य जिस बेलफास्ट शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वह राजनयिक परामर्श का ही परिणाम था जिससे दशकों से चले आ रहे संघर्ष के समापन की उद्घोषणा हुई ।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का उद्देश्य बेलफास्ट शांति समझौते के विविध पहलुओं का अध्ययन करना है । इस अध्ययन के अन्तर्गत अग्रलिखित

---

1. देखें - थामस अब्राहम, 'टू पीस मेकर्स', फ्रंटलाइन, 20 नवम्बर, 1998, पृ0 54-55

बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । प्रथम - वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का समाधान संभव हुआ ? द्वितीय, किसी संघर्ष के समाधान में राजनयिक परामर्श की क्या भूमिका होती है व किसी समझौते तक पहुंचने के लिए विभिन्न दल आपस में किस प्रकार परामर्श करते हैं ? तृतीय, परस्पर विरोधी हितों के किस प्रणाली द्वारा समायोजित किया जाता है? चतुर्थ, परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने में `व्यक्तित्वों ` की क्या भूमिका होती है, और पंचम, संवादहीनता की स्थिति में, जब कोई भी पक्ष शांति के लिए पहल न कर रहा हो, ऐसी स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका कैसे निर्णायक होती है ?

प्रथम अध्याय, उत्तरी आयरलैण्ड के संघर्ष के ऐतिहासिक पक्ष से सम्बन्धित है । इसके अन्तर्गत संघर्ष के मूल कारण तथा संघर्ष के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त यह भी समझने का प्रयत्न हुआ है कि संघर्ष में सम्मिलित देश कौन-कौन से हैं और उनके प्रतिनिधि राजनीतिक दल तथा उनके हित क्या हैं ? अध्याय के अंत में शांति के पूर्व प्रयत्नों का भी उल्लेख है ।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत शांति समझौते की पृष्ठभूमि व शांति प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया गया है । शीत युद्ध का समापन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था, जिससे पूर्व-पश्चिम के सम्बन्धों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए । उत्तरी आयरलैण्ड के सम्बन्ध में शीत-युद्ध की समाप्ति का प्रभाव, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के सैन्य संघर्ष व विचारधारा पर क्या रहा, के अध्ययन के साथ-साथ उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष में युरोपीय समुदाय की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है ।

तृतीय अध्याय, उत्तरी आयरलैण्ड शांति परामर्श प्रक्रिया की सम्पूर्ण विवेचना करता है । परामर्श के सैद्धांतिक आधारों पर समझौते की विवेचना के साथ-साथ वार्ता प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों की भूमिका का विश्लेषण व तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का अध्ययन इस अध्याय के विषय हैं ।

अंतिम अध्याय इस लघु शोध प्रबन्ध से प्राप्त निष्कर्षों से सम्बन्धित है जो उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते का मूल्यांकन करता है ।

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष : कुछ विश्लेषणात्मक तथ्य

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष की विवेचना करने वालों के मध्य, उत्तरी आयरलैण्ड विषयों के विद्वान जान व्हाइट की टिप्पणी प्रचलित रही है कि -'अपने आकार के अनुपात में उत्तरी आयरलैण्ड विश्व का सबसे बड़ा शोध-विषय रहा है ।'[2] अलस्टर स्थित विश्वविद्यालय के 1993 के शोध सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार 600 के लगभग शोध कार्यों का विषय उत्तरी आयरलैण्ड है ।[3] उपरोक्त टिप्पणी व कथन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उत्तरी आयरलैण्ड पर अध्ययन सामग्री की कोई कमी नहीं है, किन्तु इसके साथ ही इसकी बहुलता व इसकी प्रासंगिकता पर कुछ

---

2. देखें - जान व्हाइट, इन्टरप्रेटिंग नार्दन आयरलैण्ड, आक्सफोर्ड : क्लेरेंडन प्रेस, 1990, पृ0 8
3. रजिस्टर आफ रिसर्च आन नार्दन आयरलैण्ड, सेन्टर फार द स्टडी आफ कानफ्लिक्ट, यूनिवर्सिटी आफ अलस्टर, 1993

प्रश्न चिह्न भी लगते हैं । उत्तरी आयरलैण्ड सम्बन्धी एक और विद्वान एम एल आर स्मिथ के अनुसार 600 शोध कार्यों में से मात्र 35 ही प्रत्यक्षत: सम्बन्धित हैं और इन 35 में से केवल 3 संघर्ष के हिंसात्मक पहलू से जुड़े हैं ।[4] जहां एम एल स्मिथ संघर्ष पर हुए अध्ययनों में संघर्ष के सैन्य पक्ष पर कोई ध्यान न होने की कमी को सामने रखते हैं, वहीं माइकल काक्स अपनी विवेचना में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विषय के अध्ययन में उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष की प्राय: अवहेलना हुई है ।[5] काक्स इस अवहेलना के तीन कारण बताते हैं । प्रथम तो यह कि संघर्ष के आकार या इसके पैमाने के मानदण्ड के कारण इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । काक्स इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित करते हैं कि रुआंडा या बोस्निया में हो रहे संघर्षों की तुलना में उत्तरी आयरलैण्ड में 30 वर्षों में 3500 मृत्यु बहुत कम प्रतीत होती है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण शायद यह है कि 'सिप्री' ने अपनी संघर्ष सम्बन्धी रिपोर्ट में उत्तरी आयरलैण्ड को 1990 के दशक के बड़े संघर्षों में नहीं गिना ।[6]

---

4. एम एल आर स्मिथ, 'द इंटलेक्चुअल इंटरटेंमेंट आफ ए कानफ्लक्ट : द फारगौटन वार इन नार्दन आयरलैण्ड', इंटरनेशनल अफेयर्स, अंक 1, 1998, पृ0 217
5. देखें - माइकल कॉक्स, 'सिंड्रेला स्ट द बॉल', उद्धृत, पृ0 327
6. देखें - प्रिवेंटिंग डेडली कानफ्लक्ट फाइनल रिपोर्ट : कारनेजी कमीशन आन प्रिवेंटिंग डेडली कानफ्लक्ट, न्यूयार्क, कारनेजी कारपोरेशन, 1997, पृ0 12

संघर्ष के आकार के अतिरिक्त काक्स के अनुसार दूसरा प्रमुख कारण संघर्ष की प्रकृति रही है । उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष को सामान्यतया `अस्मिता` के संघर्ष के रूप में देखा गया और इसे मुख्यत: उनके लिए औचित्यपूर्ण समझा गया जिनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में न होकर साम्प्रदायिक व जातीय अध्ययन में थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उत्तरी आयरलैण्ड के प्रति उदासीनता का तीसरा कारण काक्स यह बताते हैं कि संघर्ष में हुई अमूल्य मानवीय क्षति के बावजूद वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संघर्ष ने विश्व समुदाय का ध्यान कभी उल्लेखनीय रूप में नहीं आकृष्ट किया । इस उपेक्षा का कारण संभवत: यह हो कि उत्तरी आयरलैण्ड में न तो मध्यपूर्व की तरह तेल के विशाल भण्डार थे, जिससे यह विश्व-मानचित्र पर ध्यान आकर्षित करता, न ही इसने गाजा पट्टी की तरह शरणार्थियों की विशाल संख्या को जन्म दिया और न ही दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद की तरह इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मानवाधिकार व नागरिक अधिकार जैसे मुद्दे खड़े किए । वास्तविकता तो यह है कि उपेक्षा के उपरोक्त सभी कारणों के अतिरिक्त, उत्तरी आयरलैण्ड के संदर्भ में जो तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होकर उभरता है, वो ब्रिटेन द्वारा इस विषय का कौशलपूर्ण प्रबन्धन है । वस्तुत: ब्रिटिश राज्य की यह सफलता रही कि उसने इस विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अन्य लोगों के लिए, यह समस्या या तो ब्रिटेन का आन्तरिक मामला थी, या अधिक से अधिक आंग्ल-आयरिश सम्बन्धों तक ही सीमित थी ।

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष की अध्ययन पद्धति में काक्स व स्मिथ द्वारा इंगित त्रुटियों के अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि विभिन्न विद्वानों

ने इस समस्या की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है । उदाहरण के लिए जब हम संघर्ष के इतिहास को समझने का प्रयत्न करते हैं तो पाते हैं कि एक तरफ जहां ओ लैरी और मैक गैरी ने परम्परागत इतिहास से हट कर राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया के रूप में संघर्ष को समझने का प्रयास किया है[7], वहीं फुलटान ने अंतोनियो ग्राम्शी के ऐतिहासिक वर्गों और आधिपत्य के सिद्धान्त के आधार पर आयरलैण्ड में दो विरोधी राजनैतिक - धार्मिक दलों के उदय की व्याख्या की है ।[8] गिब्बान ने राजनैतिक अर्थशास्त्र के वर्ग व उत्साह के माध्यम के आधार पर अलस्टर संघवाद के अभ्युदय व विकास का विश्लेषण किया है ।[9]

तथ्यों के उपरोक्त विवरण से यह बात प्रमाणित होती है कि उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई एक दृष्टिकोण नहीं है, अत: प्रस्तुत लघु शोध पत्र में संघर्ष के ऐतिहासिक पहलुओं की विवेचना किसी संरचनात्मक सिद्धान्त के आधार पर करके विवरणात्मक पद्धति

---

7. ब्रेडन ओ' लेरी एण्ड जान मैकगैरी, द पोलिटिक्स आफ एंटोगोनिज्म : अन्डर स्टैन्डिंग नार्दन आयरलैण्ड, लंदन, एकौलन, 1993, पृ0 2
8. जान फुलटन, द ट्रेजिडी आफ बिलीफ : डिविजन, पालिटिक्स एण्ड रिलीजन इन आयरलैण्ड, आक्सफोर्ड, क्लेरेन्डन, 1991, पृ0 4
9. पीटर गिब्सन, द औरिजन आफ अलस्टर यूनियनिज्म : द फार्मेशन आफ पाप्युलर प्रोटेस्टेंट पालिटिक्स एण्ड आइडियालोजी इन नार्दन आयरलैण्ड, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975, पृ0 1

के रूप में की गयी है । संघर्ष के समाधान के विश्लेषणात्मक पक्ष को समझने से पूर्व संघर्ष के संक्षिप्त इतिहास को जानना आवश्यक है ।

उत्तरी आयरलैण्ड की समस्या की जड़ें सुन्दर अतीत में अवस्थित हैं, जब बारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन ने आयरलैण्ड पर आक्रमण किया । सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी तक आयरलैण्ड पूरी तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया था जिसके फलस्वरूप यहां के स्थानीय कैथोलिक लोग सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेशी प्रोटेस्टेंटों द्वारा भेदभाव के शिकार होने लगे । इस असंतोष की चरम परिणति आयरिश राष्ट्रवाद व अन्ततः 1921 में आयरलैण्ड के विभाजन के साथ हुई । उत्तरी आयरलैण्ड जो प्रोटेस्टेंट बहुल था, ब्रिटेन के नियन्त्रण में रह गया, जबकि शेष आयरलैण्ड स्वतन्त्र हो गया । किन्तु विभाजन के साथ ही समस्याओं का अंत नहीं हुआ, उत्तरी आयरलैण्ड के कैथोलिक आयरलैण्ड में मिलने की आकांक्षा को निरन्तर जीवित रखे हुए थे और आयरिश संविधान द्वारा भी उत्तरी आयरलैण्ड पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया । उत्तरी आयरलैण्ड के कैथोलिक नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में विशेषकर आवासों व रोजगार के क्षेत्र में विभेदीकरण की जिस नीति का शिकार होते रहे, उसकी चरम परिणति 1969 के नागरिक अधिकार आन्दोलन के रूप में हुई, जिसने शीघ्र ही हिंसात्मक रूप को धारण कर लिया । स्थिति पर नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सेना के हस्तक्षेप ने आग में घी का काम किया और उत्तरी आयरलैण्ड में व्यवस्था भंग होने व हिंसात्मक संघर्ष का जो दौर आरंभ हुआ, वो समझौते के पूर्व तक चलता रहा ।

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष का इतिहास इसे एक ऐसे संघर्ष का रूप देता है जहां वस्तुगत और विषयगत तत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप में जुड़े

हुए हैं । वहां न केवल क्षेत्र का मुद्दा है, बल्कि इस क्षेत्र में दो संघर्षरत समुदाय जो प्रत्येक स्तर पर विभाजित हैं, उनके संघर्ष का भी मुद्दा है । ऐसे संघर्ष, जिसकी जड़ें इतनी गहरी होने के साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक - हर स्तर पर हों, उसके समाधान के प्रति समझौते की बात का आरंभ ऐसे बिन्दु से किया जाता है, जहां परस्पर विरोधी पक्षों को साथ लाया जा सके । निश्चित रूप से गहरे विवाद वाले विषयों पर तुरन्त सहमति नहीं प्राप्त की जा सकती और उन्हें जड़मूल से नहीं समाप्त किया जा सकता, किन्तु राजनयिक परामर्श व कौशल द्वारा किसी ऐसे समझौते पर अवश्य पहुंचा जा सकता है जहां किसी भी पक्ष को उसका मूल लक्ष्य न प्राप्त हो, परन्तु सामंजस्य और पारस्परिक समझ के आधार पर विषय-विशेष के संदर्भ में सहमति अवश्य बने ।[10] समझौतावादी दृष्टिकोण वस्तुगत, मुद्दा आधारित, शक्ति आधारित व व्यवहारिक होता है, जिसका लक्ष्य परामर्श द्वारा संघर्ष को क्षीण करना होता है । यहां इस लक्ष्य को प्राप्त करने में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भी महत्वपूर्ण होती है जो आवश्यकतानुसार अपने प्रभाव व शक्ति का प्रयोग कर 'परामर्श आधारित समझौते' के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है । इस अध्ययन में

----

10. देखें - डेविड ब्लूमफील्ड, 'टुवर्ड्स काम्पलिमेन्ट्रिटी इन कानफ्लिक्ट मैनेजमेंट : रिजोल्युशन एण्ड सेटलमेंट इन नार्दर्न आयरलैण्ड', <u>जर्नल आफ पीस रिसर्च,</u> भाग 32, अंक 2, 1995 पृ0 151-161, और गेरार्ड डेलान्टी, 'निगोशिएटिंग द पीस इन नार्दर्न आयरलैण्ड', <u>जर्नल आफ पीस रिसर्च,</u> भाग 32, अंक 3, 1995, पृ0 257-264

इसी सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बेलफास्ट समझौते में शामिल विभिन्न दलों को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक और व्यक्तिगत कारकों की भूमिका की विवेचना की गयी है ।

अन्त में उन कारणों का उल्लेख समीचीन होगा, जिन्होंने इस अध्ययन को प्रेरित किया । प्रथम तो यह संघर्ष समाधान व परामर्श-प्रक्रिया को समझने का एक प्रयत्न है। उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष सामाजिक संघर्षों को सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके समाधान की प्रक्रिया निश्चित रूप से विश्व के अन्य ऐसे ही संघर्षरत क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्पद हो सकती है।

द्वितीय, यह अध्ययन काक्स व स्मिथ द्वारा इंगित उस रिक्ति की पूर्ति का प्रयत्न करता है, जिसके अनुसार उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय आयामों की उपेक्षा की गयी है । उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष के समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की भूमिका प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध का एक अध्याय है ।

--

अध्याय प्रथम

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष की जड़ें यूरोपीय विकास की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया में निहित हैं, जिसने सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक पंखों का विस्तार किया । ब्रिटेन द्वारा आयरलैण्ड पर किये गये अधिकार के परिणामस्वरूप आयरलैण्ड की सामाजिक व आर्थिक संरचना पर जो प्रभाव पड़ा और उससे जिस प्रकार के सम्बन्ध निःसृत हुए, आयरलैण्ड के रक्त-रंजित संघर्ष का इतिहास वहीं से आरम्भ होता है । इस अध्याय में हम आयरलैण्ड के संघर्ष के ऐतिहासिक पहलुओं की विवेचना कर, यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि संघर्ष की जड़ें कहां से पनपीं और कैसे इतनी प्रसारित हुईं कि इन्होंने यूरोप के इतिहास की, सबसे लम्बी और रक्तरंजित समस्या का रूप ले लिया ।

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, संघर्ष के इतिहास को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम तो औपनिवेशिक युग से 1920 तक के विभाजन तक का काल, द्वितीय 1920 से असंतोष व पीड़ा तथा 1969 के नागरिक अधिकार आन्दोलन तक और तृतीय नागरिक अधिकार आन्दोलन से अब तक का काल । ऐतिहासिक रूपरेखा की विवेचना के बाद इस अध्याय में संघर्षरत प्रमुख दलों व उनके हितों की विवेचना की जाएगी और अन्त में संघर्ष-की शांति के लिए किये गये अब तक के प्रयासों का भी परीक्षण किया जायेगा ।

औपनिवेशिक राज और संघर्ष की जड़ें

पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मध्यकालीन सामंतवाद को यूरोप की नई अभ्युक्ति व्यवस्था से चुनौती मिल रही थी । इस नई व्यवस्था का आर्थिक आधार नई उभरती जनसंख्या, उत्पादक व व्यवसायिक कृषि तथा विस्तृत संचार माध्यम थे जिनके कारण यूरोप की व्यवसायिक परिधि का निरन्तर विकास हो रहा था[1] । इस व्यवस्था की राजनीतिक अभिव्यक्ति राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के निरन्तर विकास में हुई, इससे एक तरफ राजाओं और सम्राटों ने बाह्य व आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा के लिए अपनी स्थिति सशक्त करने के प्रयत्न किये, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की स्वायत्त राजनीतिक इकाईयों पर भी नियन्त्रण कर लिया ।[2] इस नयी व्यवस्था ने पुरानी चर्च (गिरिजाघर) आधारित एक्ल ईसाईवाद के स्थान पर सुधार के स्वर व राष्ट्र राज्य संस्कृति को भी उभारा ।[3]

उपरोक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यूरोप की उसकी परंपरागत सीमाओं से बाहर विस्तार है, जिसे औपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद

---

1. देखें - इमैनुअल वालर्सटाइन, द मार्डन वर्ल्ड सिस्टम, 3 भाग, न्यूयार्क : एकेडामिक प्रेस, 1975, 1980, 1988
2. चार्ल्स टिली, कोअर्सन, कैपिटल एण्ड युरोपीयन स्टेट्स, आक्सफोर्ड : बेसिल ब्लेकवेल, 1990
3. बेंडिक्ट एण्डरसन, इमेजिन्ड कम्युनिटिस : रिफ्लेक्शन्स आन द ओरिजिन एण्ड स्प्रेड आफ नेशनलिज्म, लंदन, टार्सो, 1991

के नाम से जाना जाता है ।[4] साम्राज्यवादी नीति सामान्यत: प्राथमिक रूप से आर्थिक व राजनैतिक शक्तियों व उद्देश्यों से उद्भूत हुई किन्तु धर्म भी इसका एक महत्वपूर्ण उपागम था । औपनिवेशिक प्रक्रिया के व्यापक मिशनरी उद्देश्य थे । इससे वे औपनिवेशिक प्रदेश उभरे जिन्होंने आगे चल कर स्वयं अपनी स्वतन्त्रता व राष्ट्रवाद के लिए आन्दोलन किये ।

उपरोक्त दोहरी प्रक्रिया ने ब्रिटेन व आयरलैण्ड में एक निश्चित रूप धारण किया ।[5] ग्यारहवीं शताब्दी व उसके बाद ब्रिटिश सम्राट इतना शक्तिशाली हो गया था कि इंग्लैण्ड में किसी प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक शक्ति को उभरने से रोक सके । उसका प्राथमिक उद्देश्य समुद्रतटीय उपनिवेशों, वेल्स, स्काटलैण्ड व आयरलैण्ड के ऊपर नियंत्रण करना व फ्रांस में अपने हितों की रक्षा करना था किन्तु चौदहवीं सदी में फ्रांसीसी संपीड़न का जो दौर शुरू हुआ, उससे 1540 में इंग्लैण्ड का फ्रांस में सत्ता का अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो गया और अब आंग्ल शक्ति पूरी तरह से वेल्स, स्काटलैण्ड व आयरलैण्ड में केन्द्रित हो गयी । इसी समय से अंग्रेजों ने यूरोप से बाहर अपनी शक्ति का प्रसार करना आरंभ किया, जिससे अंतत: एक विशाल क्षेत्र वाले ब्रिटिश विश्व का जन्म हुआ ।

---

4. राबर्ट बार्लेट, द मेकिंग आफ यूरोप : कान्क्वेस्ट, कालोनाइजेशन, एण्ड कल्चरल चेन्ज, 950 -1350, लंदन, पेंगविन, 1994
5. देखें - ह्युज किर्यनी, द ब्रिटिश आइल्स : ए हिस्ट्री आफ फोर नेशन्स, केम्ब्रिज : केम्ब्रिज युनीवर्सिटी प्रेस, 1989

इस नवीन विश्व में स्थापित आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के प्रारूपों के स्रोत अंग्रेजी व यूरोपीय राजनीति में मिलते हैं । दरअसल सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दी के दौरान समस्त यूरोप जिन समस्याओं से जूझ रहा था, और उनका जो समाधान हुआ, उसका ही परिणाम औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाएं थीं जिनमें राज्यों के धार्मिक व संवैधानिक प्रारूपों, उभरती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक और आर्थिक अपेक्षाएं, बढ़ते यूरोपीय संघर्ष के मध्य राज्य की सुरक्षा, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां आदि कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिनका सामना इंग्लैण्ड ने सफलतम रूप में किया । इस दौर के बाद वह राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से एकीकृत होकर निकला जिसका शासन संवैधानिक राजतंत्र के हाथों में था और जो बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था व उसकी मांगों के प्रति संवेदनशील था । ब्रिटेन आक्रामक प्रोटेस्टेंट राज्य के रूप में सामने आया जो अपने उपनिवेशों पर अनन्य अधिकार के साथ ही साथ विश्व शक्ति सन्तुलन को भी प्रभावित करता था ।[6]

सफलता के भी अपने विरोधाभास व विडम्बनाएं होती हैं जो आयरलैण्ड के एकीकरण के बाद से ही ब्रिटेन के सामने आने लगीं । यद्यपि आयरलैण्ड पर ब्रिटिश नियन्त्रण आंग्ल नार्मन युद्ध के बाद से ही आरम्भ हो गया था, फिर भी पूर्णरूपेण नियन्त्रण पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में ही जाकर स्थापित हो पाया । आयरलैण्ड के ऊपर ब्रिटिश नियन्त्रण दो बातों से प्रेरित था । एक तो इंग्लैण्ड अपने पश्चिमी किनारे

---

6. क्रिस्टोफर हिल्ल, रिफार्मेशन टू इंडस्ट्रीयल रिवोल्युशन, हार्मोन्डसवर्थ : पेंग्विन, 1969

को सुरक्षित रखना चाहता था, दूसरे वह पिछड़े, अनुत्पादक व सांस्कृतिक दृष्टि से हीन आयरलैण्ड को धर्म, राज्य, अर्थव्यवस्था व संस्कृति के क्षेत्र में विकास की अपनी अवधारणाओं की परिधि में लाना चाहता था । आयरलैण्ड के लिए आंग्ल नीति में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे किन्तु नीतियों के लक्ष्य स्पष्ट थे । इनसे इंग्लैण्ड द्वारा स्थापित धर्म को सुविधाजन्य स्थिति, स्वतंत्र भूपतियों की शक्ति को क्षीण करना, सरकार की संस्थाओं की स्थापना व प्रसार और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के साथ साथ प्रशासन को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरणा देना था । कुल मिलाकर आयरलैण्ड को आंग्ल-सम्राट के प्रमुख राजस्व स्रोत में विकसित कर अंग्रेजी भाषा व संस्कृति की स्थापना करना था[7] । समस्या तो यह थी कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवपीड़न व समझौता, राजनीतिक दबाव व नैतिक प्रेरणा आदि तत्वों में से किसको माध्यम बनाया जाय । अंग्रेजी शासन के समक्ष चिंता का विषय यह था कि अपनी नीतियों के क्रियान्वयन में अधिक गति व उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए आयरलैण्ड के लोगों के साथ काम किया जाए अथवा किसी नयी व्यवस्था को प्रायोजित किया जाए ।

आरंभिक दौर में आंग्ल नीति ने समझौते का रुख अपनाया और विधि व शासन की रूपरेखा में वहां के जमींदारों को समायोजित करने का प्रयत्न किया । सोहलवीं शताब्दी में आगे चल कर समायोजन व सामंजस्य

---

7. देखें - शीयरन ब्रेडी और रेमण्ड गिलेस्पी (संपा०), नेटिव्स एण्ड न्युकमर्स : द मेकिंग आफ आइरिश कालोनिअल सोसाइटी 1534 - 1641, डबलिन : आइरिश एकेडेमी प्रेस, 1986

की नीति का स्थान अवपीड़न व दबाव की नीति ने ले लिया । समायोजन को छोड़ कर अवपीड़न का मार्ग अपनाने के पीछे कई कारण काम कर रहे थे । आयरलैण्ड में ब्रिटेन से आया नया वर्ग, जिसमें सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सैनिक प्रशासक, पुरोहित व उनके यजमान सम्मिलित थे, इन की स्वयं को आयरलैण्ड में स्थापित करना था, जिससे वहां के स्थानीय शक्तिशाली लोगों को चुनौती मिलने लगी ।[8] ऐसी परिस्थिति में संघर्ष बहुत स्वाभाविक था और इस संघर्ष को दबाने के लिए ब्रिटिश राज को अन्ततः अपनी अवपीड़न की वही नीति अपनानी पड़ी, जिसका प्रयोग वह अन्य उपनिवेशों में कर रहा था ।

आयरलैण्ड में आये नवीन लोगों की प्रगति अत्यन्त तेज गति से हुई । ये अपनी सरकारी स्थिति व सम्राट द्वारा भूमि अधिग्रहण के विशेषाधिकार प्रदान किए जाने के कारण लाभान्वित हुए । आयरलैण्ड के उत्तरी भाग अलस्टर में इंग्लैण्ड से जो प्रोटेस्टेंट लोग आए थे, उनको वहां के स्थानीय निवासियों पर निर्णायक बढ़तप्राप्त हुई और 1641 तक उनके पास भूमि का कुल 41 प्रतिशत हिस्सा था ।[9] इसके साथ ही आयरिश संसद के दोनों सदनों में इनका बहुमत भी स्थापित हो गया । अलस्टर की जनसंख्या में प्रोटेस्टेंटों के बाहुल्य के कई कारण थे । वहां के सरकारी प्रवासियों के

---

8. देखें - ब्रेडी, 'डिक्लाइन आफ द आइरिश किंगडम' ब्रेडी व गिलेस्पी (संपा0), नेटिव्स एण्ड न्यूकमर्स, उद्धृत, पृ0 41

9. रूथ टुडली एडवर्ड्स, एन एटलस आफ आइरिश हिस्टरी, लंदन, मेथ्युन, 1973, पृ0 165-66

अतिरिक्त ऐसे लोग भी इंग्लैण्ड से आये जो या तो स्वयं आए थे, या फिर भूस्वामियों द्वारा तकनीकी कुशलता व प्रबन्धन के लिए आमंत्रित किए गए थे । आयरलैण्ड की अर्थव्यवस्था के औपचारिक औपनिवेशिकीकरण के बाद औपनिवेशिक व प्रोटेस्टेंट हितों की नींव भली भांति सुदृढ़ हो गयी ।

इस प्रकार सत्रहवीं सदी के अन्त तक आयरलैण्ड में आंग्ल सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गयी थी तथा उच्च व प्रभावशील भूमिपतियों की स्वामिभक्ति पर भी कोई शक नहीं रह गया था । अब तक आयरलैण्ड की अर्थव्यवस्था के द्वार पूरी तरह खोले जा चुके थे व इसे पश्चिमी यूरोप की पद्धति के अन्तर्गत लाने में सफलता प्राप्त हो चुकी थी । सभी प्रमुख नगरों के धनी वर्गों में आंग्ल धर्म व भाषा स्थापित हो चुकी थी, जबकि कैथोलिक चर्च रक्षात्मक स्थिति में आ गया व आयरिश संस्कृति का आत्मविश्वास व राजनीतिक सामाजिक आधार ध्वस्त हो गया ।

अगली दो शताब्दियों तक दोनों समुदायों के मध्य की खाई और चौड़ी हुई । इस काल के अन्तर्गत कई परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं । डबलिन स्थित आयरिश सरकार की जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, जिनमें आयरिश राजतन्त्र, संसद व सरकार सम्मिलित थे, ब्रिटेन की पद्धति के अनुकूल थे और कैथोलिक समुदाय के प्रतिकूल थे । 1801 में आयरलैण्ड पर नियंत्रण के प्रत्यक्ष उपाय करते हुए इंग्लैण्ड की केन्द्रीय विधि द्वारा आयरिश संसद व सरकार को समाप्त कर दिया गया व वेस्ट मिनिस्टर द्वारा अधिकार अधिगृहीत कर लिए गए ।[10]

---

10. देखें - स्लन जे. वाई, " ए कांस्टीट्युशनल बैकग्राउंड टू द नार्दन आयरलैण्ड क्राइसिस", हर माट कियोग और माइकल एच. हल्टजेल द्वारा (संपा0), नार्दन आयरलैण्ड एण्ड द पालिटिक्स आफ रिकान्सीलिएशन वाशिंगटन, वुर्डो विल्सन युनीवर्सिटी प्रेस, 1993, पृ0 35-36

इंग्लैण्ड की अवपीड़न से भरी हुई औपनिवेशिक नीति ने अन्य उपनिवेशों की तरह आयरलैण्ड में भी विद्रोह के स्वरों को जन्म दिया और उन्नीसवीं सदी के दौरान केन्द्र का नियन्त्रण उखाड़ फेंकने के लिए जो आन्दोलन हुए, उनमें निरसन आन्दोलन, 1870 में आरम्भ हुआ । होम रूल आन्दोलन, फेनियन व आयरिश गणराज्य मातृत्व वाले आन्दोलन प्रमुख थे ।[11] इनमें निरसन व होमरूल यानि स्वशासन वाले आन्दोलन तो संसदीय थे, किन्तु यूनियन व आयरिश गणराज्य मातृत्व जैसे आन्दोलन ब्रिटिश के शासन को सैन्य बल द्वारा उखाड़ फेंकने के पक्षधर थे ।

होमरूल आन्दोलन को तो व्यापक समर्थन भी प्राप्त हो रहा था और संभवत: यह सफल भी होता किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने इस आन्दोलन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया ।[12] प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1916 में ईस्टर सप्ताह में एक सैन्य विद्रोह हुआ किन्तु इसे असफल कर दिया गया व इसके नेता पकड़ लिए गए तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया । इस सैन्य विद्रोह के बाद से ही आयरिश रिपब्लिक आर्मी (आई आर ए) व उसकी राजनीतिक भुजा शिनफेन के लिए आयरिश मनों में सहानुभूति पनपी । 1918 के चुनावों में शिनफेन ने

---

11. वही, पृ0 37-41
12. देखें - यस रोसनंवाम (संपा.) अगेंस्ट होमरूल : द केस फार दि यूनियन, लंदन, फ्रेडरिक वार्नर, 1912

प्रभावशाली तरीके से पुराने आयरिश संसदीय दल को स्थानापन्न भी कर दिया और अपनी आयरिश संसद का निर्माण किया ।[13] स्वतन्त्रता के लिए जो संघर्ष आइ आर ए, शिनफेन व ब्रिटेन के मध्य चला, वह 1920 में एक संधि व इंग्लैण्ड के आयरलैण्ड विधि अधिनियम 1970 द्वारा समाप्त हो गया ।[14]

1880 से आरंभ हुए होमरूल आन्दोलन व भविष्य में इसकी संभावित सफलता से अलस्टर के प्रोटेस्टेंट बहुत सतर्क हो गए । यह प्रतिरोध की तैयारी थी और 1912 में इन दोनों समुदायों के मध्य गृहयुद्ध छिड़ने की पूरी संभावना थी किन्तु प्रथम विश्व युद्ध ने इसे टाल दिया । 1918 में अलस्टर प्रोटेस्टेंट सीधे युद्ध के स्थान पर अपने कदम पीछे हटाने लगे और उनका सारा ध्यान इस बिन्दु पर केन्द्रित हो गया कि आयरलैंड के होमरूल के लिए जो भी व्यवस्था हो उत्तरी आयरलैण्ड को उससेबाहर रखा जाए । 1920 के आयरलैण्ड शासन अधिनियम के द्वारा उनकी मांग को संरक्षण प्रदान किया गया । इस व्यवस्था द्वारा आयरलैण्ड का विभाजन कर दिया गया ।[15]

उपरोक्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि आयरलैण्ड समस्या के बीज उपनिवेशवाद के द्वारा निर्मित व्यवस्था में अंकुरित हुए और

----

13. देखें - मैरी हैरिस, "द कैथोलिक चर्च, अ माइनरिटी राइट्स एण्ड द फाउंडींग आफ द नार्दन, आयरिश स्टेट", डरमोट और हल्टलेल द्वारा (संपा.) <u>नार्दन आयरलैण्ड,</u> उद्धृत, पृ0 62-83
14. वही, पृ0 71
15. वही, पृ0 74

इस व्यवस्था ने एक ऐसे विभाजित समाज की संरचना को रूप दिया जिसमें संघर्ष प्रत्येक स्तर पर था, चाहे वो धार्मिक कारणों से हो या फिर जातीयता के आधार पर, या फिर अधिवासियों और मूल निवासियों का संघर्ष हो या उन्नति और पिछड़ेपन के सिद्धान्तों के आधार पर । इन विभिन्न स्तर पर हो रहे संघर्षों ने उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से राष्ट्रीयता और राजभक्ति के रूप में बड़े संघर्ष का रूप ले लिया ।

1921 का विभाजन

1921 की व्यवस्था ने उत्तर की प्रोटेस्टेंट बहुल छह काउंटियों को दक्षिण की शेष छबीस काउंटियों से अलग कर दिया । उत्तरी छह काउंटियों के प्रशासन को उत्तरी आयरलैण्ड का नाम दिया गया । भौगोलिक दृष्टि से यह वह भूभाग था जिसमें बहुसंख्या आसानी से ब्रिटिश संघ के साथ जोड़ी जा सकती थी । उत्तरी आयरलैण्ड में की गयी नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी जिसमें सीमित अधिकारों वाली सरकार की व्यवस्था हुई, जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्थानीय सरकार व सामाजिक सेवाओं जैसे विषय सम्मिलित थे । उत्तरी आयरलैण्ड पर अंतिम सत्ता लंदन की ही बनी रही और उत्तरी आयरलैण्ड वेस्टमिनिस्टर को अपने सांसद भेजता रहा ।[16]

---

16. देखें - स्लेन जे. वार्ड, 'ए कांस्टीट्युशनल बैकग्राउंड टू द नार्दन आयरलैण्ड क्राइसिस', उद्धृत , पृ0 33-51

TH-8247

आयरलैण्ड को उत्तरी आयरलैण्ड के बिना मिली स्वतंबता आयरिश गणराज्यवादियों के लिए अधूरी थी । संयुक्त स्वतन्त्र आयरलैण्ड की आकांक्षा उनके मन में निरन्तर जीवित रही । 1920, 1940 व 1950 में आइ आर ए द्वारा इसी आकांक्षा की पूर्ती केलिए अभियान छेड़े गए । उधर अलस्टर के बहुसंख्यक ब्रिटेन के साथ संघ के पक्षधरों को लगा कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थायी उपबन्ध व निरंतर प्रयत्न जारी रखने होंगे । एक आपात्कालीन विधान स्थायी तौर पर लागू किया गया और जो पुलिस तथा पुलिस आरक्षित बल स्थापित किया गया, उसका संगठन इस प्रकार किया गया कि प्रोटेस्टेंटों का बाहुल्य हो । स्थानीय चुनावों में भी गैरी मैण्डरिंग के माध्यम से प्रोटेस्टेंटों के पक्ष में व्यवस्था की गयी । प्रत्येक स्तर पर आर्थिक विभेदीकरण तो लागू था ही ।[17]

DISS
V,56V-95 N8 152 N9

यद्यपि संघ का रवैया अल्पसंख्यक कैथोलिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं था, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वेस्टमिनिस्टर द्वारा उत्तरी आयरलैण्ड में कुछ सामाजिक सुधार की योजनाएं लागू की गयीं जिनमें से निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान ने अपेक्षाकृत पिछड़े कैथोलिक समुदाय को लाभान्वित किया जिससे एक विशाल मध्यवर्ग का जन्म हुआ ।

---

17. देखें - जोसेफ ह्वान और जेनिफर टाड, द डायनामिक्स आफ कान्फ्लिक्ट इन नार्दन आयरलैण्ड: पावर, कानफ्लिक्ट एण्ड इमेनशीपेशन, कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पृ0 116-150

इसी मध्यवर्ग ने कालान्तर में अपने असंतोष को 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आन्दोलन के रूप में प्रकट किया ।[18]

1969 : नागरिक अधिकार आन्दोलन और उसके बाद

1950 के दशक में उत्तरी आयरलैण्ड में ऐसे वातावरण का निर्माण होने लगा जिससे यह प्रतीत हुआ कि कैथोलिकों का एक बड़ा वर्ग संयुक्त आयरलैण्ड के अपने परंपरागत लक्ष्य को प्राप्त करने के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों में अपने विरुद्ध किए जा रहे असमानता के व्यवहार को दूर करने को प्राथमिकता दे रहा था । 1967 में निर्मित उत्तरी आयरलैण्ड नागरिक अधिकार संगठन उदारवादी अधिकारों के पक्ष में अपनी आवाज बुलन्द करने लगा था । यह संगठन कैथोलिकों के प्रति नौकरियों व आवासों के आवंटन में किए जाने वाले व्यापक भेदभाव के विरुद्ध अभियान छेड़ रहा था । इस संगठन ने स्थायी आपातकालीन विधान और चुनावी धांधलियों को भी समाप्त करने की मांग की । उत्तरी आयरलैण्ड के इस नागरिक अधिकार संगठन ने अपने अभियान पद्धति की प्रेरणा अमरीकी नागरिक अधिकार आन्दोलन से प्राप्त की जिसमें विरोध प्रदर्शन, मार्च, धरना व मीडिया द्वारा प्रचार के व्यापक साधन के रूप में प्रयोग करना सम्मिलित था ।[19]

---

18. वही, पृ0 125 - 126

19. वही, पृ0 274

निरन्तर बढ़ती हुई इस नागरिक अव्यवस्था का सामना करने में स्थानीय सरकार असफल रही और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 1969 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैन्य टुकड़ियाँ उत्तरी आयरलैण्ड में भेज दीं, पर वो भी स्थिति पर काबू न पा सकी और हालात बदतर हो गए । इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर नवनिर्मित अन्त:कालीन आइ आर ए ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध हिंसात्मक प्रचार आरंभ किया ।[20] 1972 में यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगयी कि उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार स्थिति का सामना करने में पूरी तरह विफल रही है, जिसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आयरलैण्ड शासन अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरी आयरलैण्ड सरकार को निलंबित कर दिया और उत्तरी आयरलैण्ड पर वेस्टमिनिस्टर का प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया । यह स्थिति 1990 तक जारी रही ।

यद्यपि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में नागरिक अधिकार आन्दोलन बहुत हद तक सफल न हो सका और इसकी परिणति हिंसात्मक प्रतिरोध के रूप में हो गयी, फिर भी आन्दोलन की कागजी सफलता व्यापक थी । 1970 तक इसके कई उद्देश्य विचारार्थ स्वीकार कर लिए गए । इस प्रक्रिया ने आन्दोलनकारियों के उत्साह को और बढ़ाया । 1972 में आइ आर ए के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया और 1969-70 के कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दंगों का सिलसिला आगे चलकर अन्त:कालीन आइ आर ए

---

20. देखें - फ्रि. बिशप और इ. मैली - द प्राविजनल आइ आर ए, लंदन, हीनमैन, 1987

व ब्रिटिश सेना के मध्य हिंसात्मक संघर्ष में परिणत होगया । इस संघर्ष में ब्रिटिश भक्त परासैन्य दलों का खुनी हस्तक्षेप भी बीच-बीच में संघर्ष की भयावहता को बढ़ा देता था और अन्ततः इस संघर्ष का अन्त शुभ शुक्रवार समझौते के साथ ही हो पाया ।

बारहवीं सदी के बाद से लेकर अब तक के आयरलैण्ड समस्या की ऐतिहासिक विवेचना से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यातव्य हैं । 1921 तक यह प्राथमिक रूपसे आयरिश-आंग्ल समस्या थी जो आयरलैण्ड की ब्रिटेन से स्वतन्त्रता प्राप्ति पर आधारित थी । 1921 के आयरलैण्ड विभाजन के बाद यह समस्या स्वयं आयरलैण्ड में दो समुदायों केपरस्पर सम्बन्ध पर केन्द्रित हो गयी जो उत्तरी आयरलैण्ड के कैथोलिक समुदाय द्वारा सुधार व अन्य क्रांतिकारी परिवर्तनों की मांग के कारण रक्तिम संघर्ष में बदल गयी । इसके पूर्व भी कैथोलिक समुदाय द्वारा जिस स्वशासन की मांग की जा रही थी, उससे तत्कालीन स्थापित व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, जिसकी परिणति आयरलैण्ड के विभाजन के रूप में हो चुकी थी । अंत में 1969 से ब्रिटिश नीतियां उत्तरी आयरलैण्ड के भीतर स्थित कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के आपसी संघर्ष पर केन्द्रित हो गयीं ।

लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष ने विभिन्न समुदायों और शासन की शक्तियों को राजनैतिक रूप से संगठित होकर अपने हितों को साधने के लिए प्रयत्न करने हेतु प्रेरित किया । अग्रलिखित पृष्ठों में संघर्षरत मुख्य दलों और उनके लक्ष्यों की विवेचना की जाएगी ।

संघर्षरत मुख्य दल

संघवादी दल इसमें उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने उन्नीसवीं सदी में 'होम रूल' या स्वशासन का विरोध किया था और उत्तरी आयरलैण्ड केपक्ष में ब्रिटेन के साथ के समर्थक हैं। प्रमुख संघवादी दलों में अलस्टर संघवादी दल (यूयूपी) है जिसने 1921 से लेकर 1972 तक की सारी सरकारें बनायीं।[21] दूसरा संघवादी दल प्रजातांत्रिक संघवादी दल (डी यू पी) है जो कट्टर राष्ट्रवादी विरोधी प्रोटेस्टैंट समुदाय में लोकप्रिय रहा है, किन्तु चुनावों में इसे अपेक्षाकृत कम सफलताएं मिली हैं। उपरोक्त दोनों दल उत्तरी आयरलैण्ड में आयरिश गणराज्य की संलग्नता के धुर विरोधी हैं और सत्ता में किसी भी गैर संघवादी दल के साथ साझेदारी केविरुद्ध हैं। डी यू पी, यू यू पी की तुलना में अधिक उग्र हैं। इसके नेता इयान पैस्ली ने उत्तरी आयरलैण्ड शांति वार्ताओं का बहिष्कार भी किया।

राष्ट्रवादी दल राष्ट्रवादी दलों की प्रेरणा उत्तरी आयरलैण्ड व आयरिश गणराज्य का विलय रहा है।[22] इस विचारधारा को प्रस्तुत

---

21. देखें - जानेथन बारडन, ए हिस्टरी आफ अलस्टर, बेलफास्ट, ब्लैक स्टाफ, 1992
22. देखें - इमान फोनिक्स, नार्दन नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट पोलिटिक्स: पार्टीज एण्ड द कैथोलिक माइनारिटी इन नार्दन आयरलैण्ड: 1890 - 1940, बेलफास्ट, अलस्टर हिस्टारिकल फाउंडेशन, 1994

करनेवाला प्रमुख संवैधानिक दल सामाजिक प्रजातंत्र व श्रमिक दल (सोशल डेमोक्रेटिक एण्ड लेबर पार्टी एस डी एल पी) है । यह दल संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है और आंतरिक सुधारों पर बल देता है । यह दल एकीकरण का लक्ष्य रखता है किन्तु इसके लिए उत्तरी आयरलैण्ड के बहुमत का समर्थन आवश्यक समझता है । इसके प्रमुख नेता जॉन ह्युम हैं जिन्होंने उत्तरी आयरलैण्ड शांति प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और उग्र राजनीतिक दल शिनफेन को वार्ता की मेज तक ले आने में सफल रहे ।

उग्रवादी सैन्य संगठन - इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है जिसकी राजनीतिक भुजा शिनफेन है। आइ आर ए उत्तरी आयरलैण्ड केआयरिश गणराज्य में विलय का समर्थन करता है और सैन्य बल द्वारा ब्रिटिश सत्ता को उत्तरी आयरलैण्ड से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखता रहा है ।[23] स्वयं को कैथोलिकों के संरक्षक के रूप में देखने वाले इसदल ने कालान्तर में अपनी सैन्य गतिविधियों का विस्तार समूचे उत्तरी आयरलैण्ड व ब्रिटेन में कर दिया । लंदन की सड़कों को बम के धमाके से गुंजा देनेवाला यह दल लार्ड माउन्टबेटन की भी हत्या का अभियोगी है । अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित यह दल शांति प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है ।

आइ आरए के अलावा लॉयलिस्ट समूहों ने भी कई बार हिंसा का

---

23. देखें - क्विंप और मैली - प्राविजनल आइ आर ए, उद्धृत 1981

रास्ता अपनाया और हिंसा की घटनाओं की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि 1980 के बाद लायलिस्टों द्वारा रिपब्लिकंस से अधिक लोग हिंसा के शिकार हुए ।

संयुक्त ब्रिटिश राज्य

ब्रिटेन की आधिकारिक स्थिति के अनुसार उत्तरी आयरलैण्ड ग्रेट ब्रिटेन का भाग है । यह विनियोजन सभी दलों के समर्थन से हुआ था । यद्यपि ब्रिटिश लेबर पार्टी का मानना रहा है कि उत्तरी आयरलैण्ड के भविष्य का निर्णय वहां के बहुमत के निर्णय द्वारा होना चाहिए । परम्परागत दृष्टि से यह दल आयरिश एकता का समर्थन करता रहा है । उत्तरी आयरलैण्ड समस्या के समाधान की दिशा में जो भी राजनयिक परामर्श हुए (विशेषकर 1993 के काल में) उन्होंने संघवादियों व राष्ट्रवादियों के मध्य सत्ता में साझेदारी की बात सुझाई । 1985 के आंग्ल-आयरिश समझौते के तहत[24] यह निश्चय किया गया कि उत्तरी आयरलैण्ड से सम्बन्धित मामलों पर कोई भी निर्णय डबलिन सरकार से विचार कर ही लिया जाएगा ।

---

24. देखें - पाल आर्थर, "द एंग्लो-आयरिश एग्रीमेंट : ए डिवाइस फार टेरिटोरियल मैनेजमेंट", डरमाट और हाल्टजेल द्वारा (संपा.), नार्दन आयरलैण्ड, उद्धृत, पृ0 208-226

आयरिश गणराज्य

आयरिश गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 2 व 3 के अनुसार आयरलैण्ड क्षेत्रक्षेत्र में 32 काउन्टी हैं । आयरलैण्ड की सरकार ने आंग्ल-आयरिश समझौते को स्वीकार्य किया है जिसके अन्तर्गत एकता की दिशा में कोई भी प्रयत्न उत्तर आयरलैण्ड के बहुमत के निर्णय के बाद ही होगा । इसी समझौते के अन्तर्गत उत्तर आयरलैण्ड मामलों में आयरलैण्ड की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है ।[25]

विभिन्न पक्षों व उनके हितों की विवेचना से यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि परस्पर विरोधी हितों वाले इन सभी दलों में जब तक शांति के प्रयास एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं किए जाएंगे, तब तक संघर्ष के समापन की संभावना नहीं । यद्यपि संघर्ष की विभीषिका ने ब्रिटिश सरकार को शांति के प्रयास करने के लिए बाध्य किया और शांति के लिए की गयी पहल का ही परिणाम कुछ संवैधानिक सुधारों के रूप में हुआ, जिनमें 1985 का आंग्ल आयरिश समझौता और 1993 की डाउनिंग स्ट्रीट उद्घोषणा प्रमुख है । यद्यपि संघर्ष के समाधान के प्रयास 1980 के दशक से ही आरंभ हो गए परन्तु संघर्ष की प्रकृति ने शांति के प्रयासों को हमेशा विफल किया । संघर्ष के समाप्त न होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नवत हैं -

प्रथम, उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष मुख्यत: दो समुदायों (कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट) की अस्मिता का संघर्ष बन गया और इन दोनों में से कोई भी अपनी अस्मिता के कारण शांति के लिए आवश्यक थोड़ी भी नरमी को अपनी कमजोरी मानता रहा ।

---

25. देखें - गैरट फिट्जगेराल्ड, 'द ओरिजिन एण्ड रैशनल आफ द एंग्लो आयरिश एग्रीमेंट आफ 1985', डरमोट और हाल्ट जेल द्वारा (संपा.) नार्दन आयरलैण्ड, उद्धृत, पृ0 189-203.

संघर्ष के लम्बे समय तक चलने का दूसरा मुख्य कारण संघर्षरत दलों और समुदायों के मध्य किसी 'सामान्य हित' (कामन गुड) जैसी संकल्पना का अभाव होना है । विश्व में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जहां परस्पर विरोधी दलों ने अपने हित के लिए अपने अलगाव को दूर कर लिया । 1934 के बाद हुए सामाजिक संघर्ष ने आस्ट्रियन कैथोलिक दल और आस्ट्रियन सोशलिस्ट दल को यह समझने के लिए विवश कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'नाटो' और 'वारसा संधि' की सीमाओं पर स्थित आस्ट्रिया आपसी मतभेदों के साथ नहीं रह सकता और दोनों दलों ने आपस में गठजोड़ कर लिया ।[26] उत्तरी आयरलैण्ड केविभिन्न पक्षों को कभी भी किसी बाहरी शक्ति का कोई भय नहीं था और न ही उन्होंने अपने हितों को एक दूसरे के साथ समायोजित करने की कभी कल्पना भी की । इसी कारण वे कभी एक साथ शांति स्थापित करने के लिए पहल न कर सके ।

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष के लम्बे समय तक चलने का तीसरा प्रमुख कारण संघर्ष को समाप्त करने में किसी बाहरी मध्यस्थ की अभिरुचि का अभाव भी है । विगत के कुछ वर्षों को छोड़ कर (जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका ने अहम भूमिका निभायी) कभी भी किसी मध्यस्थ ने संघर्षरत विभिन्न पक्षों को एक साथ वार्ता करने पर मजबूर नहीं किया । चाहे वो मध्य-पूर्व का संघर्ष रहा हो अथवा बाल्कन जहां

---

26. देखें - अरेन्ड लिज्पहार्ट, डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसायटीज : ए कम्पेरेटिव एक्सप्लोरेशन, न्युहेवन : येल युनीवर्सिटी प्रेस, 1977, अध्याय 2 व 3

भी संघर्षरत दलों के मध्य संवादहीनता की स्थिति रही, वहां संवाद स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका बहुत अहम् रही है, परन्तु उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष के लम्बे काल तक एक ब्रिटिश राज्य का आन्तरिक विषय समझा गया और किसीतीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता का सर्वथा अभाव रहा ।

अंत में निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि औपनिवेशिक नीति ने जिस उत्तरी आयरलैण्ड समस्या के बीज बोए, उसने कालान्तर में दो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐसी कुंद मन:स्थिति का रूप धारण कर लिया कि उसके रक्तरंजित संघर्ष के अन्त होने के लिए उत्तरी आयरलैण्ड को 10 अप्रैल 1999 तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी, जब सभी परस्पर विरोधी पक्षों ने पहली बार शांति प्रक्रिया में एक दूसरे का साथ देने के लिए शुभ शुक्रवार समझौते पर अपनी सहमति दी ।

—

अध्याय 2

शांति समझौते की पृष्ठभूमि

10 अप्रैल 1998 को हुए ऐतिहासिक समझौते ने वर्षों से चले आ रहे रक्तरंजित संघर्ष की समाप्ति की उद्घोषणा कर दी। ऐसे कौन से कारण थे जिनके चलते 10 अप्रैल 1998 को शांति समझौता सम्भव हो सका, यह समझने के लिए हमें न केवल समसामयिक राजनैतिक घटनाचक्रों व संघर्षरत विभिन्न गुटों व दलों की भूमिका की विवेचना करनी होगी, बल्कि समझौते की पृष्ठभूमि और शांति के मार्ग के आरंभिक बिन्दुओं की विवेचना भी करनी होगी। आखिर कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके तहत आइ आर ए ने युद्ध विराम की घोषणा की और कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते ब्रिटिश सरकार शिनफेन जैसे कट्टरपंथी दल से बातचीत के लिए तैयार हुई, यह समझने के लिए हमें न केवल बदलती वैश्विक व्यवस्था और उसके प्रभाव को, बल्कि शांति समझौते में मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संयुक्त राज्य अमरीका के प्रभाव और साथ ही साथ यूरोपीय संघ में हो रहे परिवर्तनों और उनका शांति प्रक्रिया पर प्रभाव, इन सभी का अध्ययन करना होगा।

प्रस्तुत अध्याय में समझौते की इन्हीं पृष्ठभूमियों की विवेचना की जाएगी। आरंभ में शीत युद्ध के अंत से हुए वैश्विक परिवर्तन और उसका आइ आर ए के सशस्त्र संघर्ष व विभिन्न दलों पर प्रभाव, तत्पश्चात् अमरीका की भूमिका की विवेचना और अंत में यूरोपीय संघ के प्रभाव को समझा गया है।

बदलती विश्व-व्यवस्था और उसका प्रभाव

उत्तरी आयरलैण्ड शांति प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आये व्यापक परिवर्तनों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रभाव संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था पर पड़ा और आइ आर ए

भी इससे अछूती न रह सकी । यद्यपि उसके सशस्त्र संघर्ष के समापन व शीत युद्ध की समाप्ति में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आइ आर ए का सशस्त्र प्रचार कुछ कठिन कार्य अवश्य हो गया, क्योंकि अब इसे बहुत न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता था ।[1]

आई आर ए की ऐतिहासिक विवेचना से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जब 1970 में अन्त:कालीन आई आर ए ने अपना जीवन आरंभ किया तो वह एक पूर्णरूपेण छापामार संगठन नहीं था अपितु उसका प्राथमिक उद्देश्य उत्तर के कैथोलिकों की प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यकों द्वारा प्रस्तुत खतरों से रक्षा करना था[2] और इसके अतिरिक्त अन्त:कालीन आई आर ए के निर्माता आयरिश आन्दोलन की ऐतिहासिक स्मृतियों को पुनर्जीवित भी करना चाहते थे ।

अत: आरंभिक अन्त:कालिकों के अनुसार गणराज्यवादियों को आयरलैण्ड से बाहर देखने की कोई आवश्यकता नहीं अनुभव हुई, किन्तु जब विश्व में चतुर्दिक उत्पन्न राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों को पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका के क्रांतिकारी छात्रों का समर्थन प्राप्त होने लगा,

---

1. माइकल काक्स, 'सिन्ड्रेला एंटद बाल : एक्सप्लेनिंग द ऐण्ड आफ द वार इन नार्दन आयरलैण्ड', मिलेनियम, भाग 27, नं0 2, 1998, पृ0 330
2. आई आर ए की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए देखें - एम एल आर स्मिथ, फाइटिंग फार आयरलैण्ड ? द मिलिटरी स्ट्रैटेजी आफ द आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट, लंदन : राउटलेज, 1995 ।

तभी आई आर ए ने भी यह महसूस किया कि अपनी सैन्य आवश्यकताओं एवं राजनैतिक स्वार्थपूर्ति तथा सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयत्न के अन्तर्गत उसे विश्व के अन्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों के साथ जुड़ना होगा । विश्व के अन्य आन्दोलनों से सम्बन्ध ने आई आर ए की कार्य पद्धति पर गहन प्रभाव डाला और इससे संगठन में उन लोगों को उभरने का पर्याप्त अवसर मिला जो समाजवादी विचारों के प्रति सहानुभूति रखते थे और इस प्रकार के क्रांतिकारी संगठनों के मध्य सेतु निर्मित करना चाहते थे । आइ आर ए का शेष विश्व के आन्दोलनों से जुड़ने का एक अत्यंत महत्व-पूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि जब शीत युद्ध के अन्त के बाद विश्व के अन्य भागों में शांति स्थापना की लहर चलने लगी, तो उत्तरी आयरलैण्ड का भी इससे प्रभावित होना अवश्यम्भावी हो गया ।

आई आर ए के नेता मिशेल मेक्लाधलिन ने अपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि `जो लोग पहले ही युद्ध से शांति के कठिन संक्रमण-कालीन दौर से गुजर चुके हैं, उनके पास संभवत: आयरिशों को सिखाने के लिए कुछ हो । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विश्व के जिस भाग के लोगों ने शांति स्थापित कर ली है उन्होंने आयरलैण्ड में शांति के प्रयासों को भी अपार समर्थन दिया है ।[3] शिनफेन के अध्यक्ष गैरी एडम्स ने भी अपने लेखन में कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए कि यद्यपि आयरलैण्ड अन्य क्षेत्रों की समस्याओं से भिन्न है, तथापि यदि मध्यपूर्व व दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाधान हो सकता है तो आयरलैण्ड के लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण दिखती है । इससे भी आगे उन्होंने इस तथ्य की ओर इंगित किया कि इन संघर्षों के समाधान में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण किया है जिसमें उत्तरी आयरलैण्ड सहित तमाम

---

3. देखें, काक्स, `सिन्ड्रेला एट बाल `, पृष्ठ 330

अन्य संघर्षों के समाप्ति की संभावनाएं बढ़ी हैं।[4] संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था ने उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष को शांति के रास्ते तलाशने के लिए बहुत हद तक प्रभावित किया।

अपने आप को एक व्यापक क्रांतिकारी आन्दोलन से जोड़े रहने के कारण आयरिश गणतंत्रवादी नहीं रख सकते थे। शीत युद्ध के पूर्व आई आर ए जहां एक ऐसे व्यापक क्रांतिकारी आन्दोलन का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना था, वहीं शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन और दुनिया भर में समाजवाद के अंत के कारण वह अपना वैचारिक एवं राजनीतिक संदर्भ खोने लगी। यहां तक कि वे मित्र जो विगत में आयरिश 'भाइयों' व 'बहनों' के साथ उद्देश्यों की एकता स्थापित किए हुए थे, अब उन्हें सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने की सलाह दे रहे थे।[5] इनमें फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासिर अराफात व दक्षिणी अफ्रीकी अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला प्रमुख थे।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध का अंत, विश्व के अन्य क्षेत्रों में शांति की स्थापना एवं शांति के प्रयास और विश्व में आये एक नये वैचारिक वातावरण ने उत्तरी आयरलैण्ड में भी शांति स्थापित करने के लिए नये आयाम प्रस्तुत किये।

बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ हद तक एकाकी पड़ने के बाद भी आई आर ए ने सशक्त संघर्ष को स्थगित करने में हिचक दिखायी तो

---

4. देखें - गैरी एडम्स - सेलेक्टेड राइटिंग्स, डिंगले, बांडन, 1997, पृ0 274-75

5. एड्रियन गुमिलमे, 'कम्पेरेटिवली पीसफुल, द रोल आफ एनोलाजी इन नार्दन आयरलैण्ड्स पीस प्रासेस', केम्ब्रिज रिव्यू आफ इंटरनेशनल अफेयर्स, भाग 11, नं0 1, 1997, पृ0 28-45

यह समझना आवश्यक हो जाता है कि वह उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटेन की उपस्थिति को सिद्धांतत: किस रूप में देखती हैं।[6] गणराज्यवादियों का यह मानना रहा कि ब्रिटेन उत्तरी आयरलैण्ड में इसलिए बना हुआ है कि इससे उसे सम्पूर्ण आयरलैण्ड पर नियंत्रण करने के लिए एक आधार मिलता है। जहां तक प्रश्न आर्थिक हितों का है, स्वयं शिनफेन के 1988 के एक दस्तावेज के अनुसार उत्तरी आयरलैण्ड के लिए ब्रिटेन का आर्थिक अनुदान बहुत अधिक था। ऐसी स्थिति में उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटेन के आर्थिक हित की बात का कोई औचित्य नहीं दिखता। शिनफेन के अनुसार शीत युद्ध के दिनों में ब्रिटेन का सबसे बड़ा भय यह था कि यदि कभी आयरलैण्ड का एकीकरण हो गया तो शक्ति संतुलन उसके प्रतिकूल हो जाएगा, जबकि वह आयरलैण्ड के एक भाग को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के पक्ष में रखना चाहता था। शिनफेन का मानना था कि अपनी इस स्वार्थपूर्ति के लिए ही ब्रिटेन उत्तरी आयरलैण्ड का खर्च वहन कर रहा था।[7]

घटनाचक्रों के दौर में जब बर्लिन दीवार टूट चुकी थी व पूर्वी युरोप के साम्यवादी देशों की व्यवस्थाएं बदल चुकी थीं, तब आयरलैण्ड के भी युरोपियन क्युबा बनने की कोई उम्मीद न थी, फिर भी उत्तरी आयर-लैण्ड में ब्रिटेन की संलग्नता शिनफेन के लिए सर्वाधिक शंकास्पद विषय

----

6. विस्तृत जानने के लिए देखें, जी. आर. स्लोआन, द जिओ-पालिटिक्स आफ एंग्लो आयरिश रिलेशन इन द ट्वेंटियथ सेंचुरी, लंदन : लीस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997

7. देखें : ब्रेंडन ओ ब्रायन, द लांग वार : द आइ आर ए एण्ड शिनफेन : फ्राम आर्मड स्ट्रगल टू पीस टाक्स, डबलिन : ओ ब्रायन प्रेस, 1993 ; और इमावोन मैली व डेविड मेक्ट्रिक, द फाइट फार पीस : द सीक्रेट स्टोरी बिहाइन्ड द आयरिश पीस प्रोसेस, लंदन : हीयेनमान, 1996

था । जब उत्तरी आयरलेण्ड शांति वार्ताओं का दौर आरम्भ हुआ तो शिनफेन को ब्रिटिश इरादों के सम्बन्ध में सहमत कर पाना एक चुनौती थी । और इस परिस्थिति में सामाजिक प्रजातांत्रिक व श्रमिक दल (एस डी एल पी) के नेता जान ह्युम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनकी सबसे बड़ी भूमिका राजनयिक परामर्शकर्ता के रूप में तब उभर कर आयी जब उन्होंने 1988 से ही शिनफेन के नेता गैरी एडम्स से निरन्तर परामर्श कर अन्तत: उन्हें उत्तरी आयरलेण्ड शांति परामर्श प्रक्रिया में शामिल कर लिया ।[8] शिनफेन और एस डी एल पी के मध्य उनकी ब्रिटेन सम्बन्धी अवधारणा में एक मूलभूत अंतर यह था कि जहां शिनफेन का यह मानना था कि ब्रिटेन के पास उत्तरी आयरलेण्ड में बने रहने के पर्याप्त कारण हैं और उसे मात्र सैन्य बल से ही हटाया जा सकता है, वहीं एस डी एल पी संवैधानिक उपायों में विश्वास रखती रही और उसका यह मानना रहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही ब्रिटेन के लिए आयरलेण्ड से जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है । जान ह्युम ने एडम्स को ब्रिटेन के संदर्भ में 1985 के आंग्ल आयरिश समझौते का स्मरण कराया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि उत्तरी आयरलेण्ड का बहुमत संयुक्त आयरलेण्ड के पक्ष में होगा तो ब्रिटेन उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाएगा ।

जान ह्युम व गैरी एडम्स के मध्य परामर्श को प्रोत्साहित करना ब्रिटेन के अपने हित में था, निश्चित रूप से इससे शांति समझौते की दिशा में छाया धुआं छंट सकता था । राजनयिक परामर्श की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि ब्रिटेन राष्ट्रवादी इतिहास के प्रति अपनी समझ व उनकी भावनाओं के प्रति संवेदना प्रकट करे, इससे पारस्परिक विश्वास

----

8. देखें - जान ह्युम, 'ए न्यू आयरलैण्ड इन यूरोप', द्वारा डरमाट किओग व मिचेल एस. हल्टजल (संपा.), नार्दन आयरलैण्ड एण्ड द पालिटिक्स आफ रिकान्शिलिएशन, वाशिंगटन डी.सी., कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1993, पृ0 228-29

को निर्मित करने में सहायता मिलती। नवम्बर 1990 में उत्तरी आयरलैण्ड मामलों के तत्कालीन राज्य सचिव पीटर ब्रुक ने एक उल्लेखनीय भाषण में इस दिशा में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार की उत्तरी आयरलैण्ड में कोई स्वार्थपूर्ण रणनीति या आर्थिक अभिरुचि नहीं है।[9] यद्यपि इस वक्तव्य पर शिनफेन ने विश्वास नहीं किया और अपनी विस्फोटक गतिविधियां जारी रखीं, इतना अवश्य हुआ कि शिनफेन के वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत परामर्श के दौरान यह स्वीकार करने लगे कि यदि ब्रिटेन की तटस्थता उत्तरी आयरलैण्ड के विषय में वास्तविक हो तो आई आर ए भी सशस्त्र संघर्ष के सम्बन्धमें विचार कर सकती है। अत: जो विश्वास पीटर ब्रुक नहीं जीत सके, कालान्तर में वही विश्वास बेलफास्ट समझौते के पूर्व टोनी ब्लेयर सरकार की उत्तरी आयरलैण्ड मामलों की मंत्री मो मोलम जीत सकीं।

ब्रिटिश सरकार की राष्ट्रवादियों के सम्बंध में बदली रणनीति एवं प्रत्युत्तर में उनके सशस्त्र संघर्ष का स्थगन, किसी जादुई घटना-चक्र का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सोवियत संघ के विखण्डन के बाद पूर्व व पश्चिम में आए व्यापक परिवर्तन का ही गणराज्यीय आन्दोलन पर आया प्रभाव था। नवीन वैश्विक यथार्थ की समझ राष्ट्रवादी आन्दोलन के वरिष्ठ नेताओं के लिए प्रेरणा बनी। पुरानी राजनीतिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन की उत्तरी आयरलैण्ड में घटती अभिरुचि की संभावना शिनफेन के नेताओं को दिखने लगी। शिनफेन के वरिष्ठ नेता मार्टिन मैकगिनीज ने अपने दल के कट्टरपंथियों

----

9. देखें काक्स - सिट्रैला स्ट द बाल, पेज 334

को ब्रिटेन के साथ राजनयिक सौदे हेतु सहमत किया । हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय देते हुए ब्रिटेन तक अपना संदेश भेज दिया कि वो स्वयं भी नवीन युरोपीय व शीतयुद्धोत्तर काल में ब्रिटेन का आयरलैण्ड में कोई राजनीतिक हित नहीं है, इस बारे में निश्चित नहीं है ।[10]

शांति के पथ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, वो ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैण्ड में उसके हितों को लेकर था और डबलिन तथा लंदन की सरकारों ने इस जटिल मुद्दे को यथा संभव पूरी शक्ति से संबोधित किया । उन्होंने राष्ट्रवादियों को यह समझाने की कोशिश की कि वस्तुत: ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैण्ड में अब कोई हित नहीं है । अत: प्रत्युत्तर में हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है । दिसम्बर 1993 की डाउनिंग स्ट्रीट उद्घोषणा ने इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि `ब्रिटिश सरकार का उत्तरी आयरलैण्ड में कोई स्वार्थ-पूर्ण राजनीतिक या आर्थिक हित नहीं है ।`[11] हालांकि उद्घोषणा और तदुपरांत आई आर ए के युद्धविराम के फैसले में सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस उद्घोषणा के बिना युद्ध विराम अकल्पनीय था ।

यद्यपि आई आर ए के युद्ध विराम के फैसले से शांति स्थापना का माहौल बनने लगा, तथापि परिस्थितियों के आशानुकूल होने के बावजूद शांति प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार के शिनफेन के संदर्भ में कुछ

---

10. देखें - ब्रेडेन ओ ब्रायन, द लांग वार, पृ० 305
11. संयुक्त डाऊनिंग स्ट्रीट, उद्घोषणा, लंदन, 15 दिसम्बर, 1993 ।

पूर्वाग्रह आड़े आ रहे थे । अतीत में आइ आर ए सरकार के दो प्रमुख नेताओं की हत्या के प्रयास कर चुकी थी और उसने तत्कालीन प्रधान-मंत्री मारग्रेट थैचर के एक घनिष्ट मित्र की हत्या भी की थी । इसके अतिरिक्त सरकार निरन्तर इस बात से आशंकित थी कि शिनफेन की युद्ध विराम की घोषणा किस हद तक वास्तविक थी और यदि थी भी तो कितने दिनों के लिए इसका स्थायित्व रहेगा । शिनफेन के संदर्भ में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की यह धारणा, उसके व शिनफेन के मध्य संभाषणहीनता का परिणाम थी । ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल का उत्तरी आयरलैण्ड के प्रमुख संघवादी दल से विशेष सम्बन्ध था, जो शिनफेन का कट्टर विरोधी था, अत: ब्रिटिश सरकार शिनफेन के साथ सम्बन्ध बनाने की बहुत इच्छुक नहीं थी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रूढ़िवादी सरकार स्वयं को संघ का अभिभावक व कानून और व्यवस्था का संरक्षक समझती थी । इसलिए वह राजनयिक परामर्श की किसी ऐसी प्रक्रिया में भाग लेने को उत्साहित नहीं थी जिसमें संघ से विलग होने की आकांक्षा रखने वाले दल से उसे परामर्श करना पड़े ।

फलस्वरूप रूढ़िवादी सरकार के इस अड़ियल रवैये ने किसी भी शांति समझौते की संभावना को अत्यंत क्षीण कर दिया । ऐसे ही तनावपूर्ण व निराशाजनक बिन्दु पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप ने स्थिति को एक नवीन व महत्वपूर्ण मोड़ दिया ।[12] 10 अप्रैल 1998 को उत्तरी आयरलैण्ड के विभिन्न दलों व ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैण्ड के मध्य सम्पन्न बेलफास्ट समझौते के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका व युरोपीय संघ की भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती ।

---

12. देखें, कौनोर ओ क्लेरी, द ग्रीनिंग आफ द व्हाइट हाउस, डबलिन : गिल एण्ड मैकमिलन, 1997

संयुक्त राज्य अमरीका की भूमिका

उत्तरी आयरलैण्ड के संदर्भ में अमरीका की भूमिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलु अमरीका में बसे आयरिश मूल के लोगों का उत्तरी आयरलैण्ड के समर्थन में अपना दबाव बनाए रखना है । आरंभिक दौरसे ही आयरिश अमरीकी आयरलैण्ड के संदर्भ में अमरीकी विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे ।[13] आयरिश अमरीकनों ने राष्ट्रवादियों के समर्थन के लिए अनेक तरीके अपनाए जिनमें राष्ट्रवादी प्रचार के लिए भारी मात्रा में कोल एकत्रित करना प्रमुख रहा । आयरिश अमरीकनों की एक समुदाय के रूप में शक्ति 1980 की संयुक्त राज्य अमरीका की जनगणना के बाद सामने आयी जिसमें 40.7 मिलियन अमरीकियों ने जो कुल जन-संख्या का 18 प्रतिशत थे, ने स्वयं को आयरिश मूल से सम्बद्ध माना । प्रत्येक 4 में से 1 ने स्वयं को माता-पिता दोनों पक्षों से आयरिश माना ।[14]

जहां एक ओर आयरिश लॉबी ने अमरीकी प्रशासन की विदेश नीति को उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष के समाधान के लिए प्रभावित किया, वहीं उत्तरी आयरलैण्ड के 1968 के संकट के बाद अमरीका में कई ऐसे संगठन बने, जिन्होंने आयरिश अमरीकनों के आयरिश राष्ट्रवाद को जगाने का प्रयास किया । इन संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन है आयरिश नॉर्दन एड (नोरेड) ,

---

13. विस्तार के लिए देखें - स्ट्रीमन गुलियके, `द युनाइटेड स्टेट्स, आयरिश अमेरिकन्स एण्ड द नार्दन आयरलैण्ड पीस प्रासेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, भाग 72, नं0 3, 1996, पृ0 521-36

14. वही, पृ0 526

आयरिश नेशनल कांकस (आइ एन सी) और फ्रेन्ड्स आफ आयरलैण्ड। जिस संगठन को उत्तरी आयरलैण्ड में शिनफेन के नेतृत्व को प्रत्यक्षत: प्रभावित करने में सफलता प्राप्त हुई और जिसने आई आर ए को युद्ध विराम के लिए प्रेरित किया, वो एक नया संगठन 'अमरीकन्स फार न्यु आयरिश एजेन्डा ' (एएन आइए)था ।[15]

आई एन सी जैसे संगठनों ने वाशिंगटन स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को मुद्दा बना अमरीका के हस्तक्षेप के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की ।[16] इसको इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता डेमोक्रेटिक दल के प्रत्याशी जिमी कार्टर का समर्थन प्राप्त होने पर मिली । राष्ट्रपति चुनावों के मतदान के छ: दिन पूर्व जिमी कार्टर ने आयरिश एकता का समर्थन किया व उत्तरी आयरलैण्ड में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता प्रकट की ।[17]

यद्यपि आरंभिक दौर में आई एन सी ने मानवाधिकार को प्रमुख विषय बनाया, परन्तु बाद में कैथोलिकों के विरुद्ध रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे भेदभाव को भी इसने सफलतापूर्वक प्रचारित किया । आई एन सी का प्रमुख लक्ष्य अमरीकी सरकार द्वारा ब्रिटेन की उत्तरी

----

15. वही, पृ0 523
16. वही, पृ0 526-27
17. देखें - जैक हालैण्ड, द अमेरिकन कनेक्शन : यू एस गन्स मैनी एण्ड इन्फ्लुऐंश इन नार्दन आयरलैण्ड, हार्मोन्डसवर्थ : पैंग्विन, 1988, पृ0 127-28

आयरलैण्ड सम्बन्धी नीति को प्रभावित करना था और यह आई एन सी प्रयत्नों का ही फल था कि 1977 में आयरिश मामलों से सम्बन्धी तदर्थ कांग्रेस समिति की स्थापना हुई । रोजगार में भेदभाव सम्बन्धी उठाए गए मसले का असर 1984 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक दल पर दिखायी पड़ा और दल ने यह मांग की कि अमरीकी सरकार को इंग्लैण्ड व आयरलैण्ड के उन सारे प्रतिष्ठानों के साथ व्यापारिक आदान-प्रदान बंद कर देना चाहिए जो उत्तरी आयरलैण्ड में प्रजाति, धर्म व लिंग के नाम पर भेदभाव करते हैं ।[18] इसका त्वरित परिणाम उत्तरी आयरलैण्ड के न्यायपूर्ण रोजगार सम्बन्धी विधि के रूप में सामने आया जिसके द्वारा कैथोलिकों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त किया गया ।

उपरोक्त अध्ययन से अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता सकता है कि आयरिश अमरीकन समुदाय ने अमरीका की नीतियों को उत्तरी आयरलैण्ड के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और बदलते वैश्विक परिवेश में जब बिल क्लिंटन अमरीका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने आयरिश अमरीकनों को नाउम्मीद नहीं किया ।

बिल क्लिंटन व शांति समझौता

राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में क्लिंटन ने आयरिश-अमरीकन समूह से घनिष्ठता स्थापित की जो निश्चित रूप से चुनावी समर्थन के संदर्भ में ही थी । न्यु अमरीकन एजेण्डा फार आयरलैण्ड के नील ओ डोड, जो कि

---

18. देखें, केनेथ ए बटेश्च, द मैकब्रिज प्रिंसिपल्स एण्ड यू एस कम्पनीज़ इन नार्दन आयरलैण्ड 1991, वाशिंगटन डी सी, इन्वेस्टर रिस्पांसिबलटी रिसर्च सेन्टर, 1992, पृ० 59

आयरिश वायस नामक समाचार पत्र के संपादक थे, व लांबिइंग करने में पारंगत थे, उन्होंने 1992 के अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव-प्रचार को ऐसे ही लांबिइंग के अवसर के रूप में लिया और क्लिंटन के साथ ठोस राजनैतिक सौदेबाजी की, जिसमें शिनफेन नेता गैरी एडम्स को वीसा देने के अलावा उत्तरी आयरलैण्ड में शांति दूत की नियुक्ति व ब्रिटिश सरकार पर राजनयिक दबाव डालना सम्मिलित था, बदले में आयरिश समूह ने क्लिंटन व गोरे के सुव्यवस्थित व व्यापक प्रचार का दायित्व बखूबी संभाला ।[19]

जहां एक ओर आयरिश अमरीकी लाबी ने अमरीकी प्रशासन पर अपना प्रभाव दिखाया, वहीं दूसरी तरफ इसने उत्तरी आयरलैण्ड के दो प्रमुख नेताओं जान ह्युम और गैरी एडम्स को भी निकटलाने में सफलता प्राप्त की । नील ओ डोड ने 1993 के मई व सितम्बर में दो-दो बार उत्तरी आयरलैण्ड की यात्रा की और इस यात्रा की आन्दोलन को प्रभावित करने की क्षमता अन्त:कालीन आइ आर ए द्वारा किये गये युद्ध विराम से परिलक्षित होती है । ए एन आई प्रमुख की दूसरी उत्तरी आयरलैण्ड यात्रा के पूर्व ही ह्युम व एडम्स के मध्य समझौते की सहमति हो गयी, जिसका परिणाम ब्रिटिश व आयरिश सरकारों द्वारा 15 दिसम्बर 1993 को जारी समझौते हेतु नए सिरे से प्रयत्न करने के लिए संयुक्त उद्घोषणा थी । इस संकेत को देखते हुए आयरिश अमरीकन लाबी ने न्यूयार्क टाइम्स में एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित कराया, जिसमें संयुक्त उद्घोषणा

---

19. देखें, पीटर इवान्स, 'द न्यू यूस पीसइनीशिएटिव इन नार्दन आयरलैण्ड : ए कम्पेरेटिव एनालिसिस', यूरोपियन सेक्योरिटी, भाग 7, नं0 2, 1998, पृ0 66

का समर्थन इन शब्दों में किया गया -'आयरिश आखें शांति के लिए क्रंदन कर रही हैं और अब वो अवसर आ गया है ।'[20]

शांति केलिए होते इन तमाम प्रयासों और शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न समयानुकूल परिस्थितियों ने बिल क्लिंटन को एक ऐसा आधार दिया, जिसके ऊपर चलकर क्लिंटन ने अनेक साहसिक और अविश्वसनीय कदम उठाए ।[21] सर्वप्रथम हेमंत 1993 में उन्होंने आयरलैण्ड के लिए उच्च स्तरीय तथ्यान्वेषक दल को रवाना किया, जिसके आयरलैण्ड प्रवास के दौरान आइ आर ए ने युद्ध विराम की घोषणा की । जिसे एक उल्लेखनीय घटना के रूप में देखा जाना चाहिए । 'शांति के लिए खतरा' मोल लेने वाली अपनी कथित नीति के तहत जब बिल क्लिंटन ने शिनफेन नेता गैरी एडम्स को अमरीकी राज्य मंत्रालय, सी आई ए और एफ बी आई की सलाह के विपरीत अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अमरीका आने की अनुमति दी तो अमरीका व ब्रिटेन दोनों स्थानों पर उन पर तीक्ष्ण प्रहार हुए । क्लिंटन के इस फैसले से ब्रिटेन व अमरीका के सम्बन्धों में कड़वाहट आयी किन्तु इस फैसले का शांति की प्रक्रिया पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और आई आर ए के युद्ध विराम का फैसला बहुत हद तक इस निर्णय से प्रभावित हुआ ।[22]

---

20. गुलियके, 'द युअस, आयरिश अमेरिकन्स', उद्धृत, पृ0 525
21. देखें - कोनोर ओ क्लेरी, डेयरिंग डिप्लोमेसी : क्लिंटन्स सिक्रेट सर्च फार पीस इन आयरलैण्ड, बोल्डर : 1997
22. 'यूअस लिंक्स विथ ब्रिटेन', वर्स्ट सिंस 1773', द टाइम्स, 16 अगस्त 1996

यद्यपि क्लिंटन ने आइ आर ए के प्रथम 1993 के युद्ध विराम की उद्घोषणा में एक अहम भूमिका निभायी, तब भी शांति समझौते के सफल होने में अभी अनेक बाधाएं थीं और क्लिंटन ने तब एक मध्यस्थ के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, वो आयरिश मामलों के संदर्भ में पूर्ववर्ती अमरीकी दृष्टिकोण और नीति के बदलने का स्पष्ट परिचायक था । अमरीका ने उत्तरी आयरलैण्ड को पहले की भांति ब्रिटेन की घरेलु समस्या मानने की अपनी नीति को बदल दिया और अप्रैल 1998 में सम्पन्न शांति समझौते की प्रक्रिया में भूतपूर्व अमरीकी सीनेट के बहु-संख्यक नेता जार्ज मिशेल ने जो अहम भूमिका निभायी, वह इसी का परिणाम थी ।[23] जब समझौते के आखिरी चरणों में विभिन्न दलों में मतभेद दिखने लगा तो बिल क्लिंटन ने स्वयं इस आखिरी समय में आयरिश प्रधान मंत्री बर्ती अहरन, संघवादी नेता डेविड ट्रिम्बल और गैरी एडम्स से अपील की और अपनी मध्यस्थता से शांति प्रक्रिया के आखिरी दौर में आयी रुकावट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।[24]

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिल क्लिंटन प्रशासन की आयरिश नीति भले ही विवादास्पद प्रतीत हो, परन्तु क्लिंटन की नीति ने शांति प्रक्रिया को सफल बनाने में जो सक्रिय भूमिका निभायी, वो प्रशंसनीय है। यह इस बात का भी द्योतक है कि संयुक्त राज्य अमरीका

---

23. देखें - पाल व्यू व गोर्डन गिलिस्पी (संपा.) नार्दन आयरलैण्ड पीस प्रोसेस 1993 - 1996, लंदन, शोरिफ, 1996
24. एलिजाबेथ मीहान, 'ब्रिटिश आयरिश रिलेशन इन द कान्टेक्स आफ द यूरोपीय यूनियन', रिव्यू आफ इंटरनेशनल स्टीज ।

में आयरिश मूल के लोगों की भावनाओं और उनकी दबाव समूह के रूप में बढ़ती शक्ति को अमरीकी प्रशासन नजरअन्दाज करने की स्थिति में नहीं है ।

युरोपीय संघ और शांति प्रक्रिया

उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले विभिन्न तथ्यों में युरोपीय संघ की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है । आयरलैण्ड की परम्परागत स्थिति में आये परिवर्तन की जड़ें बहुत हद तक युरोप व आयरलैण्ड के सम्बन्धों व स्वयं युरोप में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन में निहित हैं ।[24] इस तथ्य को समझने के लिए हमें 1972-89 के पूर्व उस अतीत की ओर देखना पड़ेगा, जब आयरिश गणराज्य ने युरोपीय समुदाय में सम्मिलित होने का निर्णय लिया । आयरिश गणराज्य को युरोपीय संघ में सम्मिलित होने की प्रेरणा अपने आर्थिक राष्ट्रवाद की असफलता को समझने के बाद हुई, जो आयरलैण्ड में अपेक्षित समृद्धि लाने में विफल रहा । युरोपीय संघ में सम्मिलित होने का प्रभाव आयरलैण्ड पर अनेक रूप में पड़ा । भौतिक दृष्टि से जहां उसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी और ब्रिटेन के बाजारों पर निर्भरता घटी, वहीं उसकी आयरिश राष्ट्रीय योजना के रूप में विकास की नीति में भी बदलाव हुआ ।[25] इससे पूर्व तक आयरिश राजनीति व संस्कृति आयरिश एकता व उत्तर में ब्रिटिश

24.

25. देखें - रिचर्ड कर्नि, <u>पोस्टनेशनलिस्ट आयरलैण्ड - पालिटिक्स, कल्चर, फिलास्फी</u>, लंदन : राउटलेज, 1997

शासन के विरोध पर आधारित थी, किन्तु अब युरोप के साथ बढ़ती उसकी संलग्नता ने उसकी दृष्टि में व्यापक परिवर्तन किए । निश्चित रूप से अधिकांश आयरिश जनता के लिए युरोपीय समुदाय के साथ रह कर समान कृषि नीति, ब्रसेल्स से भारी मात्रा में अनुदान की प्राप्ति और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं को एक 'सामान्य' देश के रूप में प्रस्तुत करने की आकांक्षा ने पुरानी सभी इच्छाओं को नेपथ्य में कर दिया ।[26] इसका सीधा परिणाम आयरलैण्ड के एकीकरण के सपने के अप्रासंगिक हो जाना था क्योंकि अब युरोपीय संघ में जुड़ने से आयी समृद्धि ने जनता को एकीकरण से प्रस्तुत संभावित खतरों की ओर चैतन्य किया जिसमें उन्हें अपनी समृद्धि का संरक्षण, एकीकरण की अपेक्षा अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ ।

युरोप में सम्मिलित होने के पश्चात् आयरलैण्ड में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया में वैचारिक स्तर पर भी बदलाव आया । परंपरागत राष्ट्रवादियों व नवीन आयरिश यथार्थवादियों के मध्य एकीकरण के मसले पर गहरा मतभेद हो गया । जहां पुराने राष्ट्रवादी अभी भी आयरिश एकता के सपने देख रहे थे, वहीं अधिकतर आयरिश नागरिक शिक्षा, विज्ञान व अन्य क्षेत्रों में प्राप्त नये अवसरों की दिशा में अग्रसर थे । आयरलैण्ड की स्थिति एक बार सामान्य हो जाने के बाद आयरिश उद्योगों के संरक्षण की बजाय राज्य यहाँ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के प्रबल प्रयत्न कर रहा था। इसे परंपरावादियों ने आयरिश जीवनशैली पर प्रहार व आर्थिक स्वतन्त्रता के अपहरण के रूप में

---

26. देखें - चैलेन्जे एण्ड अपरच्युनीटिज एब्राड : व्हाइट पेपर आन फारेन पालिसी, डब्लिन, विदेश मंत्रालय, 1996, पृ० 59

देखा किन्तु डबलिन के राजनीति वर्ग व आम जनता ने ऐसी सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वागतार्थ अपने द्वार खोल दिए । ये सारे बदलाव साम्राज्यवाद की प्रकृति के खिलाफ दृष्टिकोण में आये एक व्यापक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं ।[27]

आयरलैण्ड के व्यापक युरोप के अंग बनने से न केवल वैचारिक स्तर पर अनेक . बदलाव आये वरन् आयरलैण्ड व ब्रिटेन के रिश्तों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । युरोप में सम्मिलित होने से पूर्व आयरिश गणराज्य को उत्तरी आयरलैण्ड समस्या के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ सहयोग का कोई औचित्य नहीं दिखता था किन्तु युरोपीय समुदाय में सहभागिता के अनुभव ने आयरलैण्ड व ब्रिटेन को उत्तर के विषय पर भी साथ रहने के पथ को प्रशस्त कर दिया । यद्यपि इससे उनकी अलस्टर संबंधी अपनी अवधारणाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु एक संगठन में साथ कार्य करने से परस्पर अविश्वास का विष जो दोनों देशों के सम्बन्धों को नष्ट कर रहा था, काफी हद तक कम हो गया। साथ बैठ कर विचार करने से दोनों देश इस समान निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि उनके पारस्परिक विभाजन ने न केवल उत्तरी आयरलैण्ड की समस्या को बढ़ाया है वरन् उत्तरी आयरलैण्ड की विभीषिका ने समूचे आयरलैण्ड द्वीप के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है । दोनों के समक्ष यह स्पष्ट लक्ष्य था कि उत्तरी आयरलैण्ड की अस्थिरता की स्थिति को हाथ से निकलने से रोका जाए क्योंकि यदि

---

27. पैट्रिक कीटिंग (संपा.), यूरोपियन सिक्योरिटी : आयरलैण्ड्स च्वायस, डबलिन : इंस्टीट्यूट आफ यूरोपीयन अफेयर्स, 1996

स्थिति और बिगड़ती तो वो समूचे आयरलैण्ड में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देती। देखा जाए तो 1985 के आयरिश-आंग्ल समझौते व 1993 के डाउनिंग स्ट्रीट उद्घोषणा का वास्तविक अर्थ भी यही था। हालांकि ये दोनों कदम तत्कालिक रूप से आइ आर ए की सैन्य धमकी व शिनफेन की राजनीतिक धमकी को दूर करने के लिए उठाए गये थे, फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई भी तब तक संभव नहीं था, जब तक कि आंग्ल-आयरिश सम्बन्धों में आयरलैण्ड और ब्रिटेन के युरोपीय समुदाय से जुड़ने के कारण जो दूरगामी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, वो न होता।

अन्त में आयरलैण्ड व ब्रिटेन के सम्बन्धों में जो परिवर्तन हुए, उससे गणतंत्रवाद की पुरानी आकांक्षा व आकर्षण क्षीण होने लगे। 1989 के बाद युरोप में आए विकास और परिवर्तनों ने गणराज्य के मुद्दे को काफी हद तक हाशिए पर कर दिया। युरोप में हो रहे परिवर्तनों ने बहुतों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद की कि यदि विभिन्न देश अतीत में शत्रु होने के बाद भी बदली परिस्थितियों में एक संगठन के अन्तर्गत साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर आयरलैण्ड में भी ऐसा हो सकता है।

इस समस्त प्रक्रिया के दौरान यह बात भी उभरने लगी कि जब तक उत्तरी आयरलैण्ड के दोनों समुदाय अपने मतभेदों को सुलझाने की दिशा में प्रयत्न नहीं करते, तब तक आयरिश एकता के लिए संघर्ष का कोई औचित्य नहीं दिखता। शीतयुद्ध के बाद युरोप में आये इन वैचारिक परिवर्तनों की लहर को परिलक्षित करते हुए जॉन हयुम ने सैन्य आन्दोलन के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। निरन्तर एकीकृत होते युरोप का मूल्यांकन

करते हुए उन्होंने शिनफेन से स्पष्ट कहा कि जब स्वयं संप्रभुता की अवधारणा ही प्रश्नों के घेरे में है, ऐसी परिस्थितियों में आई आर ए का पुरानी अवधारणाओं से चिपके रहना अप्रासंगिक है ।[28]

पुनश्च युरोप में आये परिवर्तनों ने गणराज्यवादी विचारधारा के सिद्धान्तों व क्रियान्वयन को किस हद तक प्रभावित किया, इसे किसी गणितीय आंकड़े में जोड़ना तो मुश्किल है परन्तु इतना अवश्य हुआ कि गणराज्यवादी विचारधारा अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुई ।इस संदर्भ में शिनफेन नेता मैकलिंघेन ने एकल यूरोपीय अधिनियम व आयरलैण्ड द्वीप पर युरोपीय समुदाय के प्रभाव को शांति समझौते के ऊपर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पहलु बताया ।[29]

----

28. डेरी जर्नल, 18 फरवरी 1994, पृ0 10

29. काक्स, सिन्ट्रेला एट द बाल , पृष्ठ 340

अध्याय 3

शांति समझौता : एक विवेचना

उपनिवेशवाद के आठ सौ साल व विभाजन के आठ दशक से चल रही समस्या का समाधान रात भर में नहीं हो सकता था, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनके कारण इस दिशा में प्रयास हुए और इन प्रयासों की सफल परिणति 10 अप्रैल 1998 को शुभ शुक्रवार समझौते के रूप में हुई । शांति प्रक्रिया आरंभ होने से लेकर शुभ शुक्रवार समझौते तक का सफर आसान नहीं था । 1921 से 'द आयरिश क्युश्चन' के रूप में उभरे खूनी संघर्ष में लगभग 3600 लोगों की जानें गयीं । 1.5 मिलियन जनसंख्या वाले देश के लिए यह संख्या छोटी नहीं है । उत्तरी आयरलैण्ड के प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य हिंसा का शिकार हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य जानता है जो यूनियनिस्ट व रिपब्लिकन हिंसा में घायल हुआ ।[1] जिस संघर्ष की जड़ें इतनी गहरी थीं, उसके समाधान का रास्ता सहज नहीं हो सकता था औरशुभ शुक्रवार समझौते की विवेचना इस सत्य को परिलक्षित करती है । इस अध्याय का उद्देश्य उस बेलफास्ट शांति प्रक्रिया की विवेचना करना है जिसके कारण समझौता संभव हो सका । संघर्ष समाधान के सैद्धांतिक पक्षों को समझते हुए बेलफास्ट शांति प्रक्रिया में हुई घटनाओं और परामर्श की प्रक्रिया में हुए समझौतों की विवेचना की जाएगी । प्रस्तुत अध्याय में संघर्ष समाधान के सिद्धान्त, परामर्श प्रक्रिया की भूमिका व समझौते में संरचनात्मक व व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव तथा परामर्श-प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ की भूमिका की विवेचना की गयी है ।

---

1. देखें, जोसेफ रुआन और जेनिफर टाड, द डायनामिक्स आफ कानफ्लिक्ट इन नार्दन आयरलैण्ड ; पावर कानफ्लिक्ट एण्ड इमेनशिपेशन, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1996 पृ० 81

संघर्ष समाधान का सिद्धांत व राजनैतिक परामर्श की प्रक्रिया

संघर्ष समाधान का तात्पर्य होता है ऐसी पद्धतियों द्वारा समस्या को समाप्त करना जो उस समस्या का उचित विश्लेषण कर सके और उसके मूल कारण तक पहुंच सके ।[2] संघर्ष की परिभाषा हम चाहे जिस प्रकार करें, चाहे इसे परिवार से ही क्यों न आरम्भ करें, यह एक ऐसी स्थिति का द्योतक है जहां पारस्परिक सम्बन्ध टूट जाते हैं और स्थापित प्रतिमानों व सत्ता के प्रति चुनौती प्रस्तुत की जाती है ... यह निराशा आधारित विरोध होता है जो विकास के अवसर की अनुपलब्धता व अस्मिता की पहचान के अभाव के कारण उत्पन्न होता है । इस संघर्ष की जड़ें वर्ग, श्रेणी, जाति, लिंग, धर्म व राष्ट्रवाद में निहित हो सकती हैं ।[3] परस्पर विरोधी हितों वाले विभिन्न पक्ष निरन्तर एक प्रकार की असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं । एक तरफ ये पक्ष जहां अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरन्तर संघर्षरत रहते हैं, वहीं दूसरी ओर ये अपने व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन से अनिश्चितता को कम करने के लिए व्यवस्था की भी स्थापना चाहते हैं ।[4] व्यवस्था की स्थापना की आकांक्षा को सम्बोधित करने वाली प्रक्रिया राजनैतिक परामर्श के रूप में सामने आती है ।

---

2. जान बर्टन, "कान्फ्लिक्ट रिजोलुशन एज ए पालिटिकल सिस्टम," पामिक वोल्कन एंड अन्य (संपा०) - द सायकोडायनामिक्स आफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भाग II, अन आफिशियल डिप्लोमेसी, लेक्सिंगटन : लेक्सिंगटन बुक, 1990, पृ० 82-83
3. वही, पृ० 20
4. वही, पृ० 71

राजनैतिक परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य परस्पर विरोधी पक्षों के मध्य की खाई को कम करना व विश्वास के वातावरण का निर्माण करना होता है । राजनैतिक परामर्श घटनाओं की अनिश्चितता को निम्नतम कर आशापूर्ण संभावनाओं में वृद्धि का कार्य करता है । राजनैतिक परामर्श विभिन्न पक्षों के मध्य एक दूसरे के प्रति समझ व सामंजस्य को विकसित करने का प्रयत्न करता है जहां परस्पर विरोधी गतिविधियों को सीमित और असंतोष को कम किया जा सके ।

एल. एन. रंगराजन ने अपनी पुस्तक (ए लिमिटेशन आफ कानफ्लिक्ट ए थ्योरी आफ बारगेनिंग एण्ड निगोशिएसन, लंदन, क्रूम हेल्म, 1985) में उन मनोवैज्ञानिक कारकों पर प्रकाश डाला है जिससे व्यक्ति समूह व राष्ट्र परामर्श की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं ।[5] लेखक के अनुसार परामर्श एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें वे लोग भाग लेते हैं जो प्राय: अविवेक-पूर्ण ढंग से कार्य व्यवहार करते हैं ।[6] लेखक को पुन: उद्धृत करते हुए यह कहा जा सकता है कि कोई भी परामर्श शून्य में कार्य नहीं करता और सभी परामर्श सातत्य परामर्श के ही अंग होते हैं । समय व इतिहास का संयुक्त प्रभाव स्मृति है और वह परामर्शकर्ता की अवधारणा व निर्णय को प्रत्येक चरण पर प्रभावित करती है ।[7]

---

5. देखें - एल ० एन० रंगराजन - द लिमिटेशन आफ कानफ्लिक्ट : ए थ्योरी आफ बारगेनिंग एण्ड निगोशिएसन, लंदन, क्रूम हेल्म, 1985, पृ० 71-88
6. वही, पृ० 6
7. वही, पृ० 77

उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष और परामर्श प्रक्रिया

रंगराजन के अनुसार कोई समझौता तभी संभव है जब

(1) राजनयिक परामर्श में भाग लेने वाले सभी पक्षों को यह विश्वास हो कि उसे समझौते से कोई लाभ मिलेगा ।

(2) परामर्श प्रक्रिया के जारी रहने से उसके लाभ की संभावना में वृद्धि होगी ।[8]

शांति समझौते की प्रक्रिया की विवेचना इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि विभिन्न दलों ने समझौते की रूपरेखा पर जिस तरह परामर्श किया, उससे अन्ततः सभी संघर्षरत दलों के मध्य एक आम सहमति का निर्माण हुआ और रचनात्मक परामर्श शैली व राजनैयिक कौशल के द्वारा विभिन्न पक्षों के लिए एक ऐसे समझौते के सम्बन्ध में विचार हुआ जिस में सभी दलों को पाने के लिए कुछ न कुछ था ।

संघर्षरत विभिन्न दल और उनके हितों के मध्य सामंजस्य

समझौते के लिए आरंभ हुई शांति प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख पक्ष निम्नलिखित थे - आयरिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, यूनियनिस्ट दल (जिसके प्रतिनिधि डेविडट्रिम्बल थे), आयरिश गणराज्यवादी दल (जिसके प्रतिनिधि जान ह्यूम थे), और आइ आर ए की राजनीतिक भुजा शिन फेन (जिसके प्रतिनिधि गैरी एडम्स व माइकल मकगिनीज थे) ।

---

8. वही, पृ० 89

ये सभी पक्ष किसी न किसी कारण एक दूसरे के विरोध में थे, परन्तु परामर्श प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा आइ आर ए के शस्त्र समर्पण के मुद्दे को लेकर थी । यूनियनिस्ट दलों की मांग थी कि जब तक आइ आर ए शस्त्र समर्पण नहीं करता है, उसे परामर्श में भाग नहीं लेना चाहिए, जबकि आयरलैण्ड व ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर की सरकार जिसने उत्तरी आयरलैण्ड मुद्दे को सर्वोपरि प्राथमिकता दी थी, शिनफेन के बगैर परामर्श को अधूरा मानती थी । सही मायनों में सरकार का दृष्टिकोण उचित भी था क्योंकि शिनफेन को यदि जनता के 19 प्रतिशत मत प्राप्त थे तो उसे आतंकवादी संगठन कहकर परामर्श प्रक्रिया से बाहर रखने का औचित्य नहीं था ।[9]

शिनफेन के परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने के मसले के अलावा शांति परामर्श प्रक्रिया में जिन मसलों विशेष के संदर्भ में सहमति पर पहुंचना आवश्यक था, उनमें सर्वप्रथम आयरिश संविधान का अनुच्छेद 2 व 3 था जिनमें उत्तरी आयरलैण्ड को आयरिश गणराज्य का भाग बताया गया है । जब तक आयरिश गणराज्य उत्तर पर अपना दावा प्रस्तुत करता रहता, यूनियनिस्टों से किसी समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, साथ ही यदि उत्तरी आयरलैण्ड के गणराज्यवादियों को समझौते की दिशा में अग्रसर करना था, तो उत्तर व दक्षिण के मध्य सम्बन्ध सूत्र को बनाए रखना आवश्यक था । उत्तरी आयरलैण्ड के यूनियनिस्ट जो ब्रिटेन के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव रखते थे, उनके लिए आयरलैण्ड के एकीकरण की

---

9. देखें - 'इंटरनेशनल पैनल आस्क्स ब्रिटेन टू हज टर्म्स आन आइ आर ए टाक्स' - न्यूयार्क टाइम्स, 24 जनवरी, 1996

कोई भी संभावना दु:स्वप्न की भांति थी, अत: उन को किसी भी समझौते के लिए तभी प्रेरित किया जा सकता था जब पूर्व व पश्चिम यानि उत्तरी आयरलैण्ड का ब्रिटेन से सम्बन्ध बना रहे ।

इस मसले के हल के लिए 1995 में प्रधान मंत्री जान मेजर और आयरिश प्रधान मंत्री अलबर्ट रेनाल्ड ने एक मशविदा का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण की रूपरेखा थी जो आयरलैण्ड और उत्तरी आयरलैण्ड के मंत्रियों की मिली-जुली संस्था के रूप में संपूर्ण आयरलैण्ड के लिए फैसले लेती । इस मसविदे का यूनियनिस्ट दल ने विरोध किया था, जबकि एस डी एल पी इसे किसी भी समझौते के मुख्य प्रावधान के रूप में देखती थी । ऐसी ही पृष्ठभूमि में इस समस्या के हल के लिए 13 जनवरी 1998 को ब्रिटिश सरकार व आयरिश सरकार ने अलस्टर शांति योजना की रूपरेखा पेश की ।[10] इस योजना के अन्तर्गत दोनों सरकारों ने जो मसविदा पेश किया, उसके तीन भाग थे । दोनों सरकारों ने यह दावा किया कि मसौदे के प्रावधान सभी पक्षों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे । इसके प्रावधान के अनुसार निम्नवत व्यवस्था की रूपरेखा बनायी गयी :

(क) अन्तर्शासकीय परिषद

यह पूर्व व पश्चिम की सरकारों, ब्रिटेन व आयरलैण्ड के मध्य सम्पर्क सूत्र की स्थापना करने के लिए थी । इसमें पूर्व से वेल्स और

---

10. देखें - 'न्यु लेबर ओल्ड स्टोरी' - द इकॉनमिस्ट, 11 जुलाई, 1998, पृ0 62

स्काटलैण्ड के निकायों कोभीसम्मिलित करने का प्रावधान रखा गया । यूयूपी के नेता डेविड ट्रिम्बल ने इसे 'द्वीपों की परिषद' कहा ।[11] द्वीपों की परिषद यूनियनिस्टों का प्रिय मुहावरा था जो उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था ।

(ख) उत्तर आयरलैण्ड की प्रस्तावित विधानसभा

विधानसभा के प्रारूप को लेकर राष्ट्रवादी व संघवादी दोनों ही सशंकित थे, किन्तु समझौते के अनुसार प्रस्तावित विधान सभा में दोनों पक्षों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होना था । हालांकि इससे निश्चित रूप से डेविड ट्रिम्बल के दल यूयूपी की शक्तियों का अवमूल्यन हो रहा था क्योंकि पिछले तीस वर्षों से संसद पर इसका एकतरफा प्रभाव था परन्तु नयी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित 108 सदस्यीय विधानसभा में इसे राष्ट्रवादियों के साथ साझेदारी करनी थी ।

(ग) उत्तर-दक्षिण निकाय

उत्तर-दक्षिण के सम्बन्धों को स्थापित करने की इस व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को तुष्ट करना था । संघवादियों को इसके विचार से ही आपत्ति थी और इसे लेकर दोनों पक्षों के मतभेद प्रेस वार्ताओं के दौरान खुलकर सामने आ गए । शिनफेन के

---

11. थॉमस अब्राहम, 'स्पदर चांस फार पीस', फ्रंटलाइन, 8 मई 1998, पृ0 53

वरिष्ठ नेता माइकल मैकगिनीज ने शांति वार्ताओं का मुख्य केन्द्र समस्त आयरलैण्ड के लिए निकाय का निर्माण बताया जबकि अलस्टर यूनियनिस्ट का कहना था कि व्यापक शक्तियों वाले आयरलैण्ड निकाय का गठन उन्हें स्वीकार नहीं होगा ।[12]

समझौते के अन्य प्रमुख प्रावधानों में व्यापारियों, पुलिस संगठनों व बलफास्ट की राजनीति-प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों की अभिव्यक्ति के लिए नागरिक मंच की स्थापना की व्यवस्था की गयी । मानवाधिकारों की रक्षा व अवसर की समानता की व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तर आयरलैण्ड, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के प्रावधान के अतिरिक्त नीति निबन्धन व अपराधिक न्याय प्रणाली के पुनर्विचार हेतु निश्चित अवधि में कार्य करने वाले स्वतन्त्र निकायों की स्थापना की व्यवस्था की गयी ।

हालांकि समझौते के विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा सभी पक्षों के हितों को समायोजित करने की कोशिश थी और उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते पर हस्ताक्षर 10 अप्रैल 1998 को होना था किन्तु इससे ठीक पहले शांति प्रक्रिया खटाई में पड़ती लगने लगी जब 4 अप्रैल 1998 को यूयूपी ने नाटकीय अल्टीमेटम जारी किया कि यदि आयरलैण्ड ने उत्तरी आयरलैण्ड पर अपना दावा छोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित योजना को स्पष्टत: घोषित नहीं किया, तो वह वार्ताओं का बहिष्कार करेगी ।[13] यदि इस

---

12. जान लाल्यड - 'ट्रिम्बल प्रिपेअरस फार हिज़ फाइनल स्टैण्ड', न्यू स्टेट्समैन, 5 फरवरी, 1999, पृ0 10-11
13. यामस अब्राहम, 'नार्दन आयरलैण्ड पीस इम्पेरिल्ड', द हिन्दू, 7 अप्रैल 1998

धमकी का क्रियान्वयन वास्तव में होता तो किसी भी समझौते पर पहुंचना, असंभव हो जाता क्योंकि संघवादियों की तरफ से परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने वाली वही एकमात्र पार्टी थी। (डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट दल के नेता इयान पेज़्ली व यूके युनियनिस्ट के प्रमुख बाब मैकांटनी दोनों ने ही परामर्श प्रक्रियाको संयुक्त आयरलैण्ड की स्थापना का माध्यम कह कर भाग लेने से इन्कार कर दिया था)। शांति प्रक्रिया में आयी उक्त अड़चन को दूर करने में अमरीकी मध्यस्थ जार्ज मिशेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और 7 अप्रैल 1998 को आयरिश प्रधानमंत्री बेर्ती एर्हेन व यूयूपी के नेता डेविड ट्रिम्बल के मध्य आयरिश संविधान के संशोधन के संदर्भ में वार्ताएं हुईं जिससे प्रोटेस्टेंटो की उत्तर दक्षिण निकाय की स्थापना के लिए सहमति हेतु विश्वास को प्राप्त करने में सहायता मिली।[14]

शांति परामर्श प्रक्रिया की विवेचना से यह साफ जाहिर होता है कि अन्तिम समाधान तक पहुंचने में विभिन्न पक्षों के बीच हुई राजनीतिक 'सौदेबाजी' व आपसी 'समझौतों' की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। सफलता के लिए शांति परामर्श में भाग लेने वाले सभी पक्षों को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा पीछे हट कर दूसरे के हितों को भी समायोजित करना पड़ा। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन उत्तर के राष्ट्रवादी दलों की स्थितियों में हुआ। शिनफेन व आइ आर ए को अंततः एक ऐसे समझौते पर सहमति प्रदान करनी पड़ी, जो उनके संयुक्त आयरलैण्ड के

----

14. रोजर मैकगिनटी, 'बिल क्लिंटन एण्ड द नार्दर्न आयरलैण्ड पीस प्रोसेस', <u>ऑसनपालिटिक</u>, नं0 3, 1997, पृ0 236

वरिष्ठ नेता माइकल मैकगिनीज ने शांति वार्ताओं का मुख्य केन्द्र समस्त आयरलैण्ड के लिए निकाय का निर्माण बताया जबकि अलस्टर यूनियनिस्ट का कहना था कि व्यापक शक्तियों वाले आयरलैण्ड निकाय का गठन उन्हें स्वीकार नहीं होगा ।[12]

समझौते के अन्य प्रमुख प्रावधानों में व्यापारियों, पुलिस संगठनों व बेलफास्ट की राजनीति-प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों की अभिव्यक्ति के लिए नागरिक मंच की स्थापना की व्यवस्था की गयी । मानवाधिकारों की रक्षा व अवसर की समानता की व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तर आयरलैण्ड, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के प्रावधान के अतिरिक्त नीति निबन्धन व अपराधिक न्याय प्रणाली के पुनर्विचार हेतु निश्चित अवधि में कार्य करने वाले स्वतन्त्र निकायों की स्थापना की व्यवस्था की गयी ।

हालांकि समझौते के विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा सभी पक्षों के हितों को समायोजित करने की कोशिश थी और उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते पर हस्ताक्षर 10 अप्रैल 1998 को होना था किन्तु इससे ठीक पहले शांति प्रक्रिया खटाई में पड़ती लगने लगी जब 4 अप्रैल 1998 को यूयूपी ने नाटकीय अल्टीमेटम जारी किया कि यदि आयरलैण्ड ने उत्तरी आयरलैण्ड पर अपना दावा छोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित योजना को स्पष्टत: घोषित नहीं किया, तो वह वार्ताओं का बहिष्कार करेगी ।[13] यदि इस

---

12. जान लालयड - 'ट्रिम्बल प्रिपेअरस फार हिज़ फाइनल स्टैण्ड', न्यू स्टेट्समैन, 5 फरवरी, 1999, पृ0 10-11
13. यामंस अब्राहम, 'नार्दन आयरलैण्ड पीस इम्पेरिल्ड', द हिन्दू, 7 अप्रैल 1998

परंपरागत लक्ष्य से एकदम भिन्न था, इसके स्थान पर उन्हें सामंजस्य व सौहार्द्रीकरण के सिद्धांत का अनुगमन करते हुए आयरिश गणराज्य के साथ संस्थात्मक सूत्र स्थापित करने का अवसर मिला । हालांकि राष्ट्रवादियों के परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और सौदे के रूप में सीमा पार की संस्थाओं का निर्माण संभव हो पाया, जिससे शासन व विधान सम्बन्धी कार्यों में आयरलैण्ड के दोनों भाग साथ-साथ कार्य कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे ।

समझौते के एक अन्य प्रावधान के तहत 108 सदस्यीय उत्तरी आयरलैण्ड विधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होना था, आनुपातिक प्रणाली के साथ-साथ यह भी प्रावधान रखा गया कि विधान सम्बन्धी कोई भी निर्णय बहुमत के साथ-साथ दोनों दलों की सहमति से किए जाएंगे । इससे कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों पक्षों का विश्वास बढ़ा कि विधायिका उनके प्रतिकूल कार्य नहीं करेगी ।[15] शिनफैन को प्राप्त मतों के अनुपात ने विधायिका की कार्यपालिका में उसके लिए दो स्थान भी सुनिश्चित कर ही दिए थे । प्रस्तावित विधायिका को उत्तर-दक्षिण मंत्रिपरिषदीय निकाय के साथ साथ कार्य करना था ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यावरण व सामाजिक कल्याण जैसे महत्व-पूर्ण विषयों पर सीमा के दोनों पार के देशों के मध्य सहयोग हो सके । इससे राष्ट्रवादियों की आयरिश गणराज्य से संलग्नता की इच्छा की भी संतुष्टि होती थी ।

---

15. 'नार्दन आयरलैण्ड्स वोट', द इकानॉमिस्ट, 23 मई 1998, पृ0 18

समझौता मसविदे पर यू यू पी के नेता डेविड ट्रिम्बल के हस्ताक्षर के पीछे स्वयं उनका अपना व्यक्तित्व व उस पर ब्रिटिश दबाव का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । एक तरफ जहां वो स्वयं अतीत की उन खोहों में नहीं जाना चाहते थे, जहां से वो यूनियनिस्ट राज्य की स्थापना हेतु वीणा उठाते व वर्तमान के शांति प्रयत्नों को दरकिनार कर द्वीप की हिंसा को जारी रखते ।[16] दूसरी तरफ डेविड ट्रिम्बल यदि शांति प्रक्रिया में भागीदार नहीं होते तो ब्रिटिश राजनीति में उनको निश्चित तौर पर निर्वासन की स्थिति का सामना करना पड़ता क्योंकि ब्रिटेन के श्रमिक दल के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने जिस तरह से उत्तरी आयरलैण्ड में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए, उससे उत्पन्न माहौल से अपने आप को दूर रखने में यूयूपी असमर्थ थी । आखिर टोनी ब्लेयर की ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिन के कारण विभिन्न विरोधी दल एक सहमति के लिए तैयार हो गए, इसे समझने के लिए हमें न केवल ब्रिटिश सरकार की भूमिका, बल्कि टोनी ब्लेयर के व्यक्तिगत प्रभाव की भी विवेचना करनी होगी ।

ब्रिटिश सरकार व टोली ब्लेयर की भूमिका

यद्यपि समझौते की दिशा में प्रयत्न पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जॉन मेजर के काल से ही आरंभ हो गया था, किन्तु वह प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी, उससे किसी सार्थक परिणति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी ।[17] किसी भी समझौते को सफल बनाने के पीछे राजनीतिक इच्छा-

---

16. जान लाल्यड, 'द वेट आफ हिस्ट्री हेंगिंग ओवर अलस्टर', न्यू स्टेट्समैन, 24 अप्रैल 1998, पृ0 14-15
17. 'वार, पीस एण्ड पालिटिक्स', संपादकीय - न्यू स्टेट्समैन, 17 अप्रैल 1998, पृ0 14

शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषकर राजनयिक परामर्श की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए तो यह अनिवार्य ही है, जब असंतोष व अविश्वास जैसी समस्याएं बार-बार सामने आती हैं । इस परिस्थिति में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार ने अपार धैर्य का परिचय दिया । स्वयं ब्लेयर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भी परामर्श प्रक्रिया से निरन्तर सम्पर्क में थे और परामर्श प्रक्रिया के दौरान आए किसी भी गतिरोध को दूर करने में अहम् भूमिका निभायी।

उत्तरी आयरलैण्ड समस्या के निदान हेतु, ब्रिटिश संसदीय चुनावों में अपनी विजय के दो सप्ताह के भीतर ही ब्रिटिश सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में टोनी ब्लेयर ने आयरिश प्रधान मंत्री जान बर्टन से भेंट की और यह आश्वासन दिया कि अलस्टर के सम्बन्ध में ब्रिटिश आयरिश सहयोग पूर्व की भांति ही जारी रहेंगे, ब्लेयर ने अपने इरादों को अलस्टर की शीघ्र यात्रा से भी प्रकट किया ।[18]

16 मई 1997 को टोनी ब्लेयर ने अपने परिचित सन्देश को दोहराते हुए यह कहा कि यदि शिनफेन युद्धविराम की घोषणा करती है तो उसे राजनयिक परामर्श की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है । विश्वास निर्माण उपक्रम के अन्तर्गत उन्होंने उत्तरी आयरलैण्ड मामलों की अपनी सरकार की सचिव मो मौलम को शिनफेन से निरन्तर परामर्श करने का निर्देश दिया ।[19] जब शांति परामर्श आगे बढ़ रहा था, उसी

---

18. वही, पृ0 14

19. वही, पृ0 14

दौरान वास्तविक आई आर ए ने बम विस्फोट द्वारा 29 लोगों की हत्या कर दी तो क्लेयर ने शांति प्रक्रिया पर उसका असर न पड़ने के लिए कहा कि "बम विस्फोटकों का उद्देश्य मात्र निर्दोष लोगों की हत्या करना नहीं था, वरन् यह शांति प्रक्रिया पर प्रहार था, इसका सबसे अच्छा प्रत्युत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि शांति प्रक्रिया को बन्द न करें अपितु उत्तर आयरलैण्ड के बेहतर भविष्य के लिए इसमें और गति लाएं और अतीत को पीछे छोड़ दें, जिसे वो (बम विस्फोट) रोकना चाहते हैं।"[20] प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार अतीत को भुला कर भविष्य की ओर ध्यान केन्द्रित करने की बात कहना, उत्तरी आयरलैण्ड के सम्बन्ध में शांति समझौते को सम्पन्न कराने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की ही अभिव्यक्ति है ।

उत्तरी आयरलैण्ड शांति परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रधान मंत्री क्लेयर का व्यक्तित्व इस प्रकार उभरता है जिसे परामर्श को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों के रूप में देखा जा सकता है । दरअसल इस सम्पूर्ण परामर्श प्रक्रिया में टोनी क्लेयर के अतिरिक्त जॉनहम्युम, डेविड ट्रिम्बल, माइकल मैकगिनीज, गैरी एडम्स सहित मो मोलम के व्यक्तित्वों का भी योगदान है जिनका उल्लेख आगे के पृष्ठों पर किया जाएगा । इसके पहले समझौते को सम्पन्न करने में अन्य तथ्यों की भूमिका पर दृष्टिपात समीचीन होगा ।

जार्टमैन व बर्टन की पुस्तक "प्रैक्टिकल निगोशिएटर" के अनुसार,

---

20. देखें, एस एल आर स्मिथ, "द इंटलैक्चुअल इंटरमेंट आफ ए कानफ्लिक्ट : द फॉरगाटेन वार इन नार्दन आयरलैण्ड", इंटरनेशनल अफेयर्स, नं01 , जनवरी 1999, पृ0 326

परामर्श तीन चरणों वाली प्रक्रिया है ।[21] प्रथम चरण में, समस्या के मूल कारण की खोज, द्वितीय उसके समाधान के प्रयत्नों का निरूपण व अन्त में उस समाधान का कार्यान्वयन । परामर्श प्रक्रिया के इस सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जब हम टोनी ब्लेयर सरकार के शांति के प्रयासों पर दृष्टिपात करते हैं तो यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि टोनी ब्लेयर की नजर में उत्तरी आयरलैण्ड की स्थिति तब तक सामान्य नहीं हो सकती, जब तक कि वहां की राजनैतिक प्रक्रिया में अतिवादियों को न सम्मिलित किया जाए । शिनफेन जैसे संगठनों को राजनीति की मुख्य धारा में लॉयलिस्ट यूनियनिस्टों के साथ सत्ता में सहभागिता में संलग्न करके ही समस्या का समाधान हो सकता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने शिनफेन को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको चार प्रकार की छूटें दीं, यद्यपि उसके द्वारा तब तक (20 जुलाई 1997 तक) युद्ध विराम की भी घोषणा नहीं की गयी थी । वस्तुत: यह प्रदत्त सुविधाएं विश्वास निर्माण उपक्रम की प्रक्रिया थीं, जिसे शिनफेन व ब्रिटिश सरकार के मध्य विश्वास स्थापित करने में वास्तविक सहायता प्राप्त हुई । शिनफेन को प्राप्त सुविधाएं निम्नवत थीं -[22]

(क) शिनफेन द्वारा लम्बे समय से की जाने वाली मांग कि परामर्श प्रक्रिया की निश्चित समयावधि हो, को स्वीकार कर लेना और 10 मई 98 का दिन जनमत संग्रह हेतु सुनिश्चित करना ।

---

21. जार्टमैन, विलियम व जान वर्टन, प्रैक्टिकल निगोशिएटर,

22. 'शिनफेन गाट ए डील', द आयरिश टाइम्स, 10 मार्च 1998

(ख) शिनफेन को ब्रिटिश सरकार द्वारा यह वचन भी दिया गया कि परा सैन्य शस्त्रों के समर्पण का मुद्दा परामर्श प्रक्रिया पर हावी नहीं होगा ।

(ग) शिनफेन को यह आश्वासन भी प्राप्त हुआ कि आई आर ए द्वारा युद्धविराम की घोषणा किए जाने के कुछ सप्ताह के भीतर ही उसे (शिनफेन को) परामर्श में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

(घ) शिनफेन को स्टारमान्ट (उत्तर आयरिश संसद) में कार्यालय अधिग्रहित करने की सुविधा दी गयी और मो मौलम ने शिनफेन कार्यालय में जा उनसे भेंट कर उसकी वैधता पर मुहर लगायी ।

शिनफेन को प्रदान की गयी उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों ने भी शिनफेन को शनैः-शनैः समझौते की दिशा में अग्रसर किया, इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय आई आर ए द्वारा दूसरे युद्ध विराम की घोषणा के एक माह के अन्दर ही परासैन्य कैदियों के मसले पर की गयी कार्यवाही है जिसके तहत 13 अति-विशिष्ट कैदियों के कड़े सुरक्षा प्रतिबन्धों में ढील दी गयी ।[23]

समझौते को प्रभावित करनेवाले व्यक्तिगत कारक :

प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर का व्यक्तित्व :

ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर को परामर्श प्रक्रिया के दौरान अपनाये गये सूत्र को पहले ही तैयार कर लेने का श्रेय दिया जा सकता है ।

---

23. 'न्यू लेबर ओल्ड स्टोरी', द इकोनमिस्ट, 11 जुलाई, 1998 पृ० 62

इसके अन्तर्गत किसी भी दल को निषेधाधिकार नहीं प्रदान किया गया और मई 1998 में जनमत संग्रह का जो निश्चय हुआ, उसमें भी समझौते के अनुसमर्थन के लिए सीधे जनता से सम्पर्क करने की इच्छा निहित थी, चाहे उत्तरी आयरलैण्ड के दल इससे सहमत हों या न हों । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आई आर ए शीघ्र युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगी तो समझौता एक्सप्रेस शिनफेन को लिए बिना ही आगे चल देगी ।[24]

परामर्श प्रक्रिया के दौरान अनिश्चितताओं की आशंका को क्षीण करने और विश्वास के वातावरण के निर्माण तथा विद्रोही दलों के विश्वास को जीतने के लिए ब्लेयर सरकार जिस स्तर तक गयी, उससे इस पर आतंकवादियों से प्रेम करने वाली सरकार होने का आरोप भी लगा ।[25] जब टोनी ब्लेयर ने 13 अक्टूबर 1997 को शिनफेन के प्रमुख परामर्शकर्ताओं गैरी एडम्स व मार्टिन मैकगिनिज से भेंट की तो यह किसी भी ब्रिटिश प्रधान मंत्री की किसी शिनफेन नेता से 70 वर्षों के बाद की गयी मुलाकात थी ।[26] जिस पर टिप्पणी करते हुए शिनफेन नेता मार्टिन मैकगिनिज ने कहा कि -'नयी श्रमिक सरकार में मिलती संभावनाओं ने मेरी उम्मीदों को पुन: प्रज्ज्वलित कर दिया है ।'[27]

---

24. 'नार्दन आयरलैण्ड : फ्राम प्रोसेस टू प्रासेस', द इकॉनमिस्ट, 18 अप्रैल, 1998, पृ0 16
25. वही, पृ0 18
26. जान लाल्यड, 'इनटू द वेरी लास्ट लैप', न्यू स्टेट्समैन, 11 जनवरी , 1998, पृ0 16
27. वही, पृ0 16

उपरोक्त सकारात्मक विकासों से, शांति परामर्श प्रक्रिया के सम्बन्ध में जैसे ही यह लगने लगा कि यह सही दिशा में अग्रसर है, वैसे ही अलस्टर में धार्मिक हिंसा पुन: भड़क उठी और ऐसा प्रतीत हुआ कि शांति परामर्श प्रक्रिया टूट जाएगी । लापलिस्ट वालन्टियर फोर्स द्वारा शिनफेन नेता गैरी एडम्स की भतीजी के पति की हत्या और प्रत्युत्तर में लापलिस्ट वालन्टियर फोर्स के सदस्य बिल राइट की हत्या से जो शृंखला आरंभ हुई, उससे शांति प्रयत्नों पर बड़े-बड़े प्रश्न चिह्न लग गये ।[28] जले पर नमक यह हुआ कि इसके तुरन्त बाद प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट पार्टी शांति परामर्श प्रक्रिया से बाहर निकलने की धमकी देने लगी, जिसे देखते हुए शिनफेन के एक परामर्शी कर्ता गैरी केली ने यहां तक कह डाला कि परामर्श प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है ।[29]

ऐसी जटिल परिस्थिति में एक बार फिर टोनी ब्लेयर ने तारणहार की भूमिका निभायी और अपनी जापान यात्रा के दौरान, सुदूर टोकियो से 'दूरभाष राजनय/कूटनीति' द्वारा किये गये अपने प्रयत्नों से एक माह के अन्तराल के बाद वार्ता प्रक्रिया को पुन: आरंभ कराने में सफलता प्राप्त की ।

विश्वास निर्माण उपक्रम के एक दूसरे प्रयास के अन्तर्गत टोनी ब्लेयर ने सेंट पैट्रिक दिवस के दिन अमरीका स्थित ब्रिटिश दूतावास में उत्तरी आयरिश मामलों की सचिव मो मौलम, शिन फेन प्रमुख गैरी एडम्स

---

28. 'नार्दन आयरलैण्ड : फ्राम प्रोसेस टू प्रोसेस', द इकॉनमिस्ट, 18 अप्रैल 1998, पृ0 16

29. वही, पृ0 16

व एस डी एस पी के नेता जान ह्यूम व डेविड ट्रिम्बल जो यू यु पी के प्रमुख हैं, को एक साथ दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया जिसे राजयिक क्षेत्र में एक विशेष अवसर के रूप में देखा गया जब उत्तरी आयरलैण्ड शांति स्थापना से संबंधित सभी पक्षों को एक साथ वार्ता हेतु लाया गया । इसके पूर्व सभी पक्षों के मध्य परामर्श परस्पर होने के स्थान पर ब्रिटिश सरकार से ही अधिक था ।[30]

मार्च 1998 में जब रिपब्लिकन और यूनियनिस्ट अभी एक दूसरे से बहुत दूर खड़े थे, ऐसे में टोनी ब्लेयर की यह घोषणा कि वे समझौते के कगार पर खड़े हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य लग सकता है, किन्तु यह सभी पक्षों को साथ ला समझौते की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ने की उनकी दृढ़इच्छाशक्ति को भी प्रतिबिम्बित करता है ।

मो मौलम की भूमिका

उत्तरी आयरलैण्ड शांति परामर्श प्रक्रिया की सफलता के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की उत्तरी आयरिश मामलों की सचिव व ब्रिटेन की ओर से शांति प्रक्रिया की परामर्शकर्ता सुश्री मो मौलम के विशिष्ट योगदान का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है । शांति प्रक्रिया के दौरान सशक्त व प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरी मौलम के राजनयिक कौशल व परामर्शदामता ने टोनी ब्लेयर के राष्ट्रवादियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों को स्पष्टतया प्रभावित किया । यद्यपि शिनफेन से युद्ध विराम के सम्बन्ध में किये गये परामर्श और डाउनिंग स्ट्रीट में उसके नेताओं के स्वागत जैसे

---

30. जान लाल्यड, 'अल्स्टर्स हार्ट स्टापिंग मूवमेंट', न्यू स्टेट्समैन, 3 अप्रैल, 1998, पृ० 11

मुद्दों ने मो मौलम की भूमिका को विवादास्पद बनाया और उन्हें कड़ी आलोचना का पात्र बनना पड़ा ।[31] आलोचनाओं से मौलम की अनौपचारिक व स्पष्टवादिता वाली कार्य प्रणाली अप्रभावित रही । वो इसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार का विरोध झेलने को तत्पर रहीं, यहां तक कि उन्होंने अपने प्रेस कार्यालय के प्रमुख एंडी वुड को अपनी कार्य शैली से असहयोग के कारण अलग भी कर दिया ।[32]

मो मौलम की गणराज्यवादियों के प्रति पूर्वाग्रह युक्त शैली ने उन्हें परामर्श प्रक्रिया में सहयोग के लिए प्रेरित किया । 'न्यू स्टेट्समैन' को दिये साक्षात्कार में मौलम की शिनफेन के बारे में की गयी टिप्पणी उपरोक्त पंक्ति की पुष्टि करती है । उन्होंने कहा कि 'वे धैर्य से सुनते हैं और गलतियों को बताये जाने पर उसे सही करने को तत्पर रहते हैं ।'[33] एक अन्य अवसर पर शिनफेन नेता गैयर्ड एडम्स को अपनी बाहों के घेरे में ले, उन्होंने जिस आत्मीयता का प्रदर्शन किया, उसकी अपेक्षा उनके पूर्ववर्तियों से कदापि नहीं की जा सकती थी ।

मौलम के पक्ष में लाभप्रद तथ्य यह भी रहा कि वे उत्तरी आयरलैण्ड की राजनीति से व्यक्तिगत रूप से भली भांति परिचित थीं । स्थितियों के वास्तविक अभिज्ञान के कारण वह वहां के राजनीतिज्ञों व आम जनता से

----

31. वारेन हाज, 'मो्स् विनिंग स्टाइल', फ्रंट लाइन, 19 जून, 1998, पृ0 64

32. वही, पृ0 64

33. स्टीव रिचर्ड द्वारा साक्षात्कार, न्यू स्टेट्समैन, 31 अक्टूबर 1997, पृ0 20-21

प्रत्यक्षत: संवाद स्थापित करने में सफल रही । 'न्यु स्टेट्समैन' के जान लायड को दिये साक्षात्कारमें उन्होंने यह भी कहा कि वे उत्तरी आयरलैण्ड की जनता के निरंतर सम्पर्क में हैं और उनकी शांति स्थापना की अदम्य भावना को समझ कर वे इस दिशा में आगे प्रयत्न के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं ।[34] शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने ही परामर्श प्रक्रिया को कई अवसरों पर स्थगित होने से बचाया । 3 मार्च 1997 को जब हत्या के 3 आरोपों के कारण शिनफेन को अस्थायी तौर पर परामर्श प्रक्रिया से बहिष्कृत कर दिया गया तो मौलम इस बहिष्कार को वापस लेने के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहीं । उनका स्पष्ट मानना था कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार के अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने चाहिएं ।

इसी प्रकार जनवरी 1998 में जब शांति वार्ताओं को भंग करने के लिए लायलिस्ट परासैन्य संगठन से धमकी मिली और उन्होंने शांति प्रक्रिया के प्रति अविश्वास व्यक्त किया तो मौलम ने इस संगठन के सदस्यों से शांति प्रक्रिया में बाधा न डालने के उद्देश्य से सीधे जेल में परामर्श करने का विवादास्पद निर्णय लिया और अंतत: उन्हें (लायलिस्ट) भी परामर्श की मेज तक लाने में सफलता प्राप्त की । साथ ही मौलम ने उन्हें यह भली-भांति अनुभव करा दिया कि परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित हुए बिना किसी की कोई भी मांग सुनना असंभव है । उन्होंने धैर्य से सुनते हुए उनकी मांगों को नोट भी किया किन्तु प्रत्युत्तर में किसी सुविधा या छूट का वचन नहीं दिया, उन्होंने यह साफ-साफ कहा कि उनके कैदियों की रिहाई, वार्ता प्रक्रिया की सफलता पर निर्भर करेगी । मौलम ने अतिवादियों से यह

---

34. वही, पृ0 21

दो टूक कहने में कोई परहेज नहीं किया कि 'हिंसा से आप को महज़ जेल ही नसीब होगी ।'[35]

मो मौलम की भूमिका का मुल्यांकन करते हुए यह कहना समीचीन होगा कि उनके अटल किन्तु सौम्य, आक्रामक हुए बिना उनकी दृढ़ता, दबाव के स्थान पर परामर्श की उनकी प्रेरणात्मक शैली ने उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते को संभव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

जान ह्युम का व्यक्तित्व और उनका शांति प्रक्रिया पर प्रभाव

उत्तरी आयरलैण्ड शांति परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने में उत्तर के सबसे बड़े कैथोलिक गणराज्यवादी दल एस डी एल पी के नेता जान ह्युम की भी महत्ती भूमिका है । जान ह्युम हालांकि शीघ्र क्रोध करने वाले और यूनियनिस्टों के कड़े आलोचक के रूप में जाने जाते रहे हैं ।[36] वे उत्तर में किसी भी परिवर्तन को संवैधानिक माध्यमों से लाने के पक्षधर हैं । जान ह्युम का सबसे बड़ा योगदान, पिछले कई वर्षों से शिनफेन से निरन्तर संवाद स्थापित करना और उसे राजनीतिक परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत करा लेने में सफल हो जाना है ।[37] 1993 में शिन फेन

---

35. वही, पृ0 21

36. जान लाल्यड, 'आयरलैण्ड्स अनसर्टेन पीस', फॉरेन अफेयर्स, भाग 77, नं0 5, पृ0 109

37. वही, पृ0 109

के साथ परामर्श का जान ह्युम का निर्णय शांति प्रक्रिया का निर्णायक मोड़ था, जिसे आयरिश गणराज्य, ब्रिटेन की सरकार के साथ-साथ अमरीका का समर्थन भी प्राप्त था । ह्युम की प्राथमिकता उत्तरी आयरलैण्ड में शांति स्थापना थी, इसलिए इस प्रक्रिया में बाधा न आने देने के लिए, उन्होने एस डी एल पी के उप प्रमुख सीम्स मौलम को यूयूपी के नेता डेविड ट्रिम्बल से परामर्श करने के लिए नियुक्त किया ताकि उनके और ट्रिम्बल के व्यक्तिगत कड़वे सम्बन्धों का प्रभाव शांति परामर्श प्रक्रिया पर न पड़े ।[38] इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विधायिका के शासकीय कार्य को सुचारू रूप से चलने देने के लिए भी उप प्रमुख के पद के लिए भी मौलम का ही नामांकन हुआ, क्योंकि इन दोनों नेताओं में पर्याप्त पारस्परिक समझ विकसित हो चुकी थी ।[39]

गैरी एडम्स और शांति प्रक्रिया

आई आर ए की राजनीतिक भुजा शिनफेन के नेता गैरी एडम्स की छवि करिश्माई व्यक्तित्व की है जिसने ब्रिटिश दूरदर्शन के माध्यम से आयरिश मामले को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा दिया । माना जाता है कि आई आर ए के निर्णयों में भी उनकी अहम् भूमिका होती है । आई आर ए से बिलग हुए उसके पूर्व सदस्य सीन आ' कालंघन ने अपनी शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक 'द इनफार्मर' में गैरी एडम्स को अत्यंत सावधान व कुशल रणनीतिज्ञ बताया है, जिसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का

---

38. जान लाल्यड, 'अल्स्टर्स हार्ट स्टापिंग मूवमेंट', न्यू स्टेट्समैन, 3 अप्रैल 1998, पृ0 10

39. वही, पृ0 10

समयानुकूल सटीक प्रयोग करना तो आता ही है साथ ही ब्रिटेन, आयरलैण्ड व अमरीकी सरकारों के साथ शांति-सहयोग की बातें करना भी बखूबी आता है।[40]

शिनफेन का आधार जो पहले कैथोलिक श्रमिक वर्ग तक ही सीमित था, उसे बुर्जुआ मध्य वर्ग तक पहुंचाने में एडम्स की प्रमुख भूमिका रही है, अपनी अमरीका यात्रा के दौरान एडम्स अलस्टर में विदेशी निवेश की सिफारिश करते दिखे। संभवत: इसीलिए अलस्टर में यह भी सुनने में आने लगा है कि बी एम डब्ल्यु चलाइए, और एडम्स को मत दीजिए।[41] विदेशी निवेश व मतदाताओं की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि उत्तरी आयरलैण्ड में शांति स्थापित हो, इस तथ्य को जानते हुए गैरी एडम्स द्वारा शांति परामर्श प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लेना आश्चर्यचकित नहीं करता।

शांति परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने के बाद आतंकवादी से शांति निर्माता बनने तक की यात्रा में गैरी एडम्स ने यह समझ लिया कि यद्यपि उत्तरी आयरलैण्ड से सम्बन्धी प्रस्तावित समझौता संयुक्त आयरलैण्ड की स्थापना नहीं करता, जिसके लिए उन्होंने शस्त्र उठाया था किन्तु उन्होंने यह भी ठीक से समझ लिया कि यह समझौता भविष्य में इस तरह की किसी प्रक्रिया पर रोक भी नहीं लगाता। प्रस्तुत समझौते में स्पष्ट

---

40. वही, पृ० 11

41. वही, पृ० 10

प्रावधान था कि उत्तरी आयरलैण्ड की स्थिति से सम्बन्धित कोई भी अंतिम निर्णय वहां की जनता के बहुमत से ही होगा । इस प्रावधान के आधार पर रुडम्स निश्चित रूप से भविष्य में कभी न कभी प्रोटेस्टेंटों को आयरिश एकीकरण के लिए सहमत होने की आशा रख सकते थे । 26 मार्च 1993 को 'फाइनेंशियल टाइम्स' में ब्रिटिश सरकार से लीक होकर जो समाचार प्रकाशित हुआ, उससे रुडम्स की आशाओं में वृद्धि हुई होगी।[42] उक्त समाचार के अनुसार ब्रिटिश सरकार, उत्तरी आयरलैण्ड की स्थिति के संदर्भ में (वह ब्रिटेन का भाग रहे या न रहे) प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर जनमत संग्रह कराने के निर्णय के बारे में विचार कर रही है, निश्चित रूप से जनमत संग्रह का परिणाम कभी संयुक्त आयरलैण्ड के पक्ष में भी जा सकता था ।

डेविड ट्रिम्बल के व्यक्तित्व का प्रभाव

उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों में डेविड ट्रिम्बल का नाम महत्वपूर्ण है, जो उत्तरी आयरलैण्ड के प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्टों के सबसे बड़े नेता हैं । अपने दल यू यी पी के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने से पहले वे कट्टर 'आरेन्ज मार्चर[+]' थे और इन मार्चों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध के विरुद्ध थे ।[43] बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए वे शांति की स्थापना की आवश्यकता को समझने लगे और

---

42. वही, पृ० 11

43. जान लायड, 'आयरलैण्ड्स अनसर्टेन पीस', पृ० 118

\+ आरेन्ज मार्च प्रोटेस्टेंट द्वारा विजयोत्सव के रूप में जुलूस निकालने की प्रक्रिया है, जिसे कैथोलिक समुदाय अपनी हार की स्मृति के रूप में देखता है । यह जुलूस कैथोलिक बहुत क्षेत्रों से निकलकर इमुक्टी चर्च तक जाता है जिससे हिंसा भड़कने की पर्याप्त संभावना रहती है ।

इस दिशा में हर संभव प्रयत्न किया, यद्यपि इस प्रयत्न के पीछे ब्रिटिश सरकार का दबाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसे कोई भी यूनियनिस्ट दल अस्वीकार नहीं कर सकता।[44] यूनियनिस्ट दलों द्वारा ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त होने का तात्पर्य है, ब्रिटिश राजनीति से उनका पृथक्कीकरण, जो वे कभी नहीं चाहते। डेविड ट्रिम्बल समूची परामर्श प्रक्रिया के दौरान आई आर ए व शिव फेन को लेकर तीव्र आपत्तियां व्यक्त करते रहे। वे आई आर ए द्वारा शस्त्र समर्पण किये जाने के पूर्व शिन फेन को परामर्श प्रक्रिया से बाहर ही रखना चाहते थे जो टोनी ब्लेयर के प्रभाव के कारण हो नहीं पाया, किन्तु डेविड ट्रिम्बल के कड़े रुख के कारण आई आर ए पर शस्त्र समर्पण के लिए निरन्तर दबाव बना रहा और इस दबाव में वे अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहे। डेविड ट्रिम्बल का समझौते के बाद प्रभाव में आने वाली कार्यपालिका का प्रथम मंत्री नियुक्त होना निश्चित था, जिससे उनकी स्थिति पर्याप्त प्रभावशाली थी और इसका उपयोग करते हुए उन्होने कार्यपालिका के मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ पूर्व शर्तें निर्धारित कीं और इस संदर्भ में टोनी ब्लेयर से लिखित आश्वासन भी प्राप्त कर लिया।[45] पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार, सत्ता में सहभागी सभी पक्षों को हिंसा का मार्ग छोड़ अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी पड़ेगी और शांति तथा प्रजातन्त्र के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आई आर ए द्वारा शस्त्र समर्पण में विलम्ब, उक्त शर्त के अनुसार शिनफेन को कार्यपालिका में शामिल होने से निश्चित रूप से रोकेगा।[46]

---

44. वही, पृ0 110

45. 'अण्टरनेटिव अल्स्टर', द इकॉनमिस्ट, 19 सितम्बर, 1998, पृ0 70

46. वही, पृ070

संयुक्त राज्य अमरीका की मध्यस्थता का शांति प्रक्रिया पर प्रभाव

उत्तरी आयरलैण्ड शांति वार्ता को सम्पन्न कराने में अमरीका की मध्यस्थता ने निर्णायक भूमिका निभायी । अमरीकी सीनेटर जार्ज मिशेल जो शांति परामर्श प्रक्रिया के अध्यक्ष थे, ने मध्यस्थ की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया । जार्ज मिशेल, सभी पक्षों को धैर्य-पूर्वक सुनने और उनकी स्थिति समझने तथा मित्रवत व्यवहार के कारण सभी पक्षों के विश्वसनीय बने ।[47]

राजनीतिक परामर्श में मध्यस्थ की भूमिका : सैद्धांतिक पक्ष

राजनयिक परामर्श में मध्यस्थ की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, उसे प्राय: विवादित पक्षों को उनके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से हटने के लिए तैयार करना पड़ता है । मध्यस्थ की भूमिका के सम्बन्ध में लिखते हुए जार्ट मैन व टावेल ने कहा है[48] कि मध्यस्थ, विवादित पक्षों के मध्य परामर्श हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है । इसका उद्देश्य अस्थिरता की आशंका को कम कर स्थायित्व की संभावना में वृद्धि करना है । लेखक द्वय के अनुसार मध्यस्थता अपनी कार्य नीति में संचार (कम्युनिकेशन), सूत्री-करण (फार्म्युलेशन) व प्रभाविता कौशल का प्रयोग करती है ।

संचार के अन्तर्गत जहां समस्या के संदर्भ में विभिन्न पक्षों की उससे सम्बन्धित अवधारणाओं को मूल रूप में एक दूसरे तक सम्प्रेषित करना

---

47. रोजर मैक्वीटी, "बिल क्लिंटन एण्ड दि नार्दन आयरलैण्ड पीस प्रोसेस", उद्धृत, पृ0 236
48. देखें, जार्टमैन विलियम व सादिया टावेल, इन्टरनेशनल मेडिएशन इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, बोल्डर, वेस्टव्यू 1985

होता है, वहीं सूत्रीकरण के माध्यम से मध्यस्थ समस्या को सुलझाने के लिए सभी पक्षों को प्रेरित करने के साथ साथ समाधान की प्रविधियां भी सुझाता है । तीसरा और अंतिम चरण मध्यस्थ के प्रभाविता कौशल से सम्बन्धित है, जिसके अंतर्गत मध्यस्थ अपनी शक्ति का प्रयोग पक्षों को समझौते तक लाने और संघर्ष से दूर हटाने में करता है ।

जार्ट मैन व टावेल के अनुसार मध्यस्थता की भूमिका का अंतिम तत्व 'विभिन्न दलों की अवधारणाओं में परिवर्तन कराना है ।' किसी भी मध्यस्थता को प्रभावी सिद्ध होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक अन्य विद्वान जैकब बर्कोविच ने तीन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया है ।[49] प्रथम परिस्थिति में समस्या से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों की पहचान व उनकी विशेषताएं सम्मिलित हैं यानि जब विवादित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की पहचान हो जाए तो मध्यस्थता की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं । द्वितीय परिस्थिति के अनुसार मध्यस्थता तभी प्रभावी हो सकती है, जब उसका कार्य क्षेत्र मध्यम व लघु शक्तियों के बीच हो, महाशक्तियां किसी भी प्रभाव का प्रतिरोध करने में सक्षम होती हैं । अतः वहां मध्यस्थता अप्रभावी है । मध्यस्थता की तीसरी व अंतिम परिस्थिति बर्कोविच के अनुसार सम्बन्धित पक्षों के मध्य शक्ति का अन्तर है, मध्यस्थता की सफलता की संभावना तब बढ़ जाती है जब समस्या से सम्बन्धित पक्षों की शक्तियों में अपेक्षाकृत कम अन्तर हो ।

मध्यस्थता की सफलता को प्रभावित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मध्यस्थ की स्वयं की पहचान व विशेषताएं हैं । मध्यस्थता एक स्वैच्छिक

---

49. देखें, जैकब बर्कोविच, सोशल कानफ्लिक्ट्स एण्ड थर्ड पार्टीज़, स्ट्रैटेजी आफ कानफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बोल्डर, वेस्टव्यू, 1984

प्रक्रिया है, जो सभी विवादित पक्षों की सहमति व विश्वास के आधार पर ही क्रियान्वित हो सकती है, इसीलिए मध्यस्थ का स्वतंत्र व विश्वसनीय समझा जाना आवश्यक है, जो मध्यस्थ की सत्ता, संसाधन व क्षमता पर निर्भर करता है ।

मध्यस्थता के उपरोक्त सिद्धान्तों को उत्तरी आयरलैण्ड की अमरीकी मध्यस्थता के संदर्भ में देखने पर उसकी सफलता के कारणों की विवेचना सरलता से हो सकती है । जहां तक मध्यस्थ की पहचान, शक्ति, क्षमता व संसाधन का प्रश्न है, अमरीका शीत युद्धोत्तर विश्व की एकमात्र महाशक्ति है जो विश्व के किसी भी कोने की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है । अमरीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्तरी आयरलैण्ड के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था करवाना उसकी क्षमता का ही द्योतक है जिसने उत्तरी आयरलैण्ड के राजनीतिज्ञों को निश्चित रूप से प्रभावित किया ।[50]

बर्कोविच द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता की परिस्थितियों के लिए उत्तरी आयरलैण्ड उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । यूनियनिस्ट व रिपब्लिकन दलों के रूप में दो प्रमुख परस्पर विरोधी दल तथा उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटिश व आयरिश सरकारों की संलग्नता के कारण कुल चार पक्षों की स्पष्ट पहचान थी जिनके मध्य परामर्श आरंभ कराना था । जहां तक पक्षों के बीच शक्ति सन्तुलन का प्रश्न है, यह रिपब्लिकन व यूनियनिस्ट दलों के मध्य आंका जाय तो उत्तरी आयरलैण्ड के चुनावों में उन्हें लगभग समान मत

---

50. देखें, काक्स, 'सिण्ड्रेला स्ट द बाल', उद्धृत, पृ0 34।

प्राप्त हुए थे और दोनों दल जनता की शांति स्थापना की आकांक्षा को समझते हुए परामर्श के लिए बाध्य भी हुए।[51] ब्रिटेन शीतयुद्ध के काल का अमरीका का मित्र रहा है और प्राय: उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका के सहयोगी के रूप में देखा जाता है। अत: उसके द्वारा अमरीकी मध्यस्थता के लिए किसी आपत्ति का प्रश्न ही नहीं था। आयरलैण्ड शांति स्थापना के लिए ब्रिटेन का हरसंभव सहयोग कर रहा था। अत: उसने भी अमरीकी मध्यस्थता को पूरा सहयोग दिया।

जार्ट मैन व टाक्ल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कि मध्यस्थता विवादित पक्षों के मध्य परामर्श हेतु उत्प्रेरक का कार्य करती है। अमरीकी मध्यस्थता के संदर्भ में पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। अमरीका, उत्तरी आयरलैण्ड के विवादित पक्षों के मध्य संवाद स्थापित करने का प्रबल पक्षधर था और उसने ऐसे किसी भी वातावरण के निर्माण में ब्रिटेन का सहयोग किया, जिससे परामर्श को प्रोत्साहन मिले। जान ह्युम को शिनफेन से परामर्श आरंभ करने के लिए अमरीका द्वारा दी गयी प्रेरणा व सहयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वयं राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 'शांति के लिए खतरा' मोल लेने वाली अमरीकी नीति के अंतर्गत विश्व में शांति, स्थिरता व प्रजातंत्र की रक्षा के कथित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व के कई देशों में अमरीकी मध्यस्थता का समर्थन कर रहे थे।[52]

---

51. वही, पृ0 341

52. देखें, अर्नेस्ट इवान्स, 'द यू एस पीस इनिशिएटिव इन नार्दन आयरलैण्ड', ए कम्परेटिव एनालिसस', यूरोपीयन सेक्योरिटी, भाग 7, नं0 2, 1998, पृ0 65

जार्टमैन ने मध्यस्थ की भूमिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलु "विवादित पक्षों की अवधारणाओं में परिवर्तन कराना" बताया है। अमरीका ने उत्तरी आयरलैण्ड विवाद से सम्बद्ध पक्षों को परामर्श द्वारा उनकी पूर्व स्थितियों में परिवर्तन हेतु प्रेरित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी। शिनफेन जो उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटेन की उपस्थिति को समाप्त करने व संयुक्त आयरलैण्ड की स्थापना के अतिरिक्त अन्य किसी मुद्दे पर संवाद स्थापित करने के विरुद्ध थी, और यूनियनिस्ट दल जिस के लिए शिनफेन अस्पृश्य आतंकवादी थी और जो आयरिश गणराज्य से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहती थी, वो सब अंतत: न सिर्फ एक दूसरे से विवादित मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु सहमत हुए, वरन् एक ऐसे समझौते को भी स्वीकृति प्रदान दी, जो उनके पूर्व घोषित लक्ष्यों से दूर था। समझौते के प्रावधान न तो उत्तरी आयरलैण्ड में ब्रिटेन की उपस्थिति को कम करते थे, न ही आयरलैण्ड को उत्तरी आयरलैण्ड से अलग करते थे। ऐसी परिस्थिति में सम्पन्न समझौता निश्चित रूप से सभी पक्षों की परिवर्तित अवधारणाओं का ही परिणाम है।

जार्टमैन व टावेल ने मध्यस्थता की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख किया है जो उत्तरी आयरलैण्ड के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं। उनका मानना है कि ऐसे विवाद जो सुरक्षा व सैन्य विषयों से सम्बन्धित होते हैं, वहां मध्यस्थता की सफलता की संभावना अधिक होती है, जबकि धार्मिक व वैचारिक आधारों वाले संघर्ष में इसकी भूमिका सीमित हो जाती है। देखा जाय तो मध्यस्थता प्राय: समस्या के सतह पर तैर रहे प्रश्नों को सम्बोधित करती है और विवादित पक्षों को समाधान की दिशा में साथ प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है किन्तु वह समस्या के मूल कारणों को समाप्त नहीं कर सकती।

उत्तरी आयरलैण्ड के विवाद की जड़ें सुदूर इतिहास में निहित हैं जिनका प्रमुख आधार धर्म व विचारधारा है, ऐसे जटिल विवाद में मध्यस्थता इन मूल कारणों पर परामर्श नहीं कर सकती थी, उसने स्थिति को `सामान्य` करने के लिए `सत्ता में सहभागिता` सिद्धान्त के आधार पर राजनीतिक स्तर पर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया ।

और अन्त में, परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक है कि उस में भागीदार सभी पक्षों को प्रतीत होना चाहिए कि समझौते द्वारा उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हुआ है । उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते में सभी पक्षों को संतुष्ट करने के तत्व विद्यमान हैं । गणराज्यवादियों के लिए सीमा पार उत्तर-दक्षिण संस्था की स्थापना जहां उन्हें संयुक्त आयरलैण्ड की दिशा में प्रथम चरण लग सकता है तो यूनियनिस्टों के लिए आयरलैण्ड गणराज्य द्वारा उत्तर के कुछ प्रान्तों पर से संवैधानिक दावे को छोड़ना एकीकरण की किसी भी संभावना को सदैव के लिए समाप्त करने जैसा है । इसके अतिरिक्त उत्तर-दक्षिण निकाय की व्यवस्था से उन लोगों को प्रोत्साहन मिला जो अलस्टर को आयरलैण्ड का भाग बनाना चाहते हैं जबकि पूर्व-पश्चिम निकाय उन लोगों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है, जो ब्रिटेन के साथ स्थायी सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं ।

निष्कर्ष

इस अध्याय के समापन के समय तक शुभ शुक्रवार समझौते को लगभग एक वर्ष हो जाएगे और अध्ययन के निष्कर्ष के लिए ये आवश्यक है कि शांति समझौते के बाद उसके क्रियान्वयन से संबंधित घटनाओं का परीक्षण किया जाए।

समझौते को द्वीप के दोनों भागों में अपार समर्थन मिला। उत्तरी आयरलैण्ड में 71 प्रतिशत लोगों ने समर्थन में मत दिया (81 प्रतिशत लोगों ने मत दिया, जो एक रिकार्ड है), जबकि आयरलैण्ड गणराज्य में 94 प्रतिशत (54 प्रतिशत लोगों ने मत दिया) मतदाताओं ने समर्थन में मत दिया।[1]

यद्यपि जनमत संग्रह के परिणामों ने शांति समझौते के पक्ष को आवश्यक जनसमर्थन देकर शांति की आशाओं को मजबूत किया, किन्तु पिछले एक वर्ष की घटनाएं शांति समझौते के क्रियान्वयन के मार्ग में आशा और निराशा दोनों ही को उजागर करती रही हैं।

----

1. देखें - डिक वाल्श, 'द रिजल्ट आफ फ्राइडेज़ वोट्स व्येर वन आफ द ग्रेट मोमेंट्स आफ आयरिश हिस्ट्री - वी हैव हैड 1916 एण्ड द ट्रिटी एण्ड नाउ दिस', आयरिश टाइम्स, 25 मई, 1998, पृ0 59

जहां एक ओर कैदियों की रिहाई और ब्रिटिश सेना के स्थानान्तरण जैसे मुद्दे आसानी से पूरे किए गए, वहीं ऐसे अनेक मुद्दे सामने आ गए हैं जिन्होंने समझौते के सफल क्रियान्वयन पर प्रश्न चिह्न लगा दिया । एक ओर शाही अल्स्टर कांस्टेबलरी और उत्तरी आयरलैण्ड पुलिस की भूमिका को लेकर शिनफेन और अन्य लायलिस्ट समूहों में गंभीर मतभेद है,[2] वहीं दूसरी ओर शांति प्रक्रिया में दो प्रमुख बाधाएं आरेन्ज जुलूस और आइ आर ए के शस्त्रों के समर्पण के मुद्दे को लेकर उपस्थित हो गयी हैं ।

आरेन्ज यात्राएं प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में आयोजित की जाती हैं, जो पोर्ट डाउन शहर के कैथोलिक बहुल क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं । प्रोटेस्टेंट आरेन्ज व्यवस्था यात्रा को अपना मुल अधिकार समझते हैं, जबकि कैथोलिक इनका विरोध करना अपना नैतिक अधिकार । पिछले तीन वर्षों से इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में जो हिंसात्मक लड़ाई हुई है, उससे इस वर्ष भी हिंसा भड़कने का अन्देशा है । ये उम्मीद की जा रही है कि जन प्रतिनिधि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में आपस में एक शांतिपूर्ण हल खोजने में सफल हो जायेंगे ।[3]

----

2. देखें - नील जारमैन और डोमिनिम ब्रायन, <u>फ्राम रायट्स टू रायट्स : नेशनलिस्ट परेड्स इन द नार्थ आफ आयरलैण्ड</u>, कालोरिन, सेन्टर फार द स्टडी आफ कानफलिस्ट, 1998

3. देखें - सैमस डयुन, 'नार्दन आयरलैण्ड : ए प्रामिशिंग आर पार्टीशन पीस', <u>जर्नल आफ इन्टरनेशनल अफेयर्स</u>, भाग 52, अंक 2, 1999, पृ0 728

शस्त्र समर्पण का मुद्दा शांति प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा बन गया है और इसने समझौते के विभिन्न पक्षों के मध्य एक तरह से संवादहीनता की स्थिति ला दी है । आइ आर ए का यह मानना है कि बन्दूकें और प्लास्टिक विस्फोटक अब प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे और यह एक तरह से शस्त्रों का समर्पण ही है ।शिनफेन ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया कि पिछले दो वर्षों से शस्त्रों का प्रयोग न होना एक तरह से शस्त्र समर्पण ही है । यद्यपि समझौते के प्रावधानों के अनुसार मई 2000 तक आइ आर ए को शस्त्र समर्पण करना है परन्तु इसमें कोई पहल न होने से यू यू पी के नेता डेविड ट्रिम्बल जो इस मुद्दे पर पहले ही सशंकित थे, अब बहुत ही कठोर व अड़ियल रुख अपना चुके हैं । वे आइ आर ए के शस्त्र समर्पण के बिना मंत्रिमण्डल में शिनफेन को शामिल किये जाने के सख्त खिलाफ हैं, जबकि शिनफेन बिना मंत्रि-मंडल में सम्मिलित हुए इस दिशा में कोई प्रयत्न करता नहीं दिख रहा। ट्रिम्बल के कड़े रुख के पीछे उनकी अपनी राजनैतिक विवशता भी है क्योंकि उनके द्वारा शांति प्रक्रिया के दौरान उठाये गये कदमों को यू यू पी के कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं मिला था । अब आरेंज यात्रा के साथ-साथ शस्त्र समर्पण केविवाद ने यू यू पी के कट्टरपंथियों के पक्ष को मजबूत कर दिया है । साथ ही अपने दल के दूसरे प्रमुख नेता जेफ्री डोनाल्डसन की वापसी (डोनाल्डसन ने शांति प्रक्रिया के बहिष्कार के मुद्दे पर दल छोड़ दिया था) से ट्रिम्बल बिना कड़ा रुख अपनाये अपने आप को दल के सर्वोच्च नेता के रूप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।[4]

---

4. देखें - 'ट्रिम्बल टू टेक हार्ड लाइन', द हिन्दू, 4 अप्रैल, 1999

यद्यपि शस्त्र समर्पण के मुद्दे पर शिनफेन ने नरमी बरती है और अपने वचन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भी कैदियों की रिहाई जैसे विषय पर सक्रियता दिखाकर शांति समझौते के प्रति अपनी निष्ठा की है, परन्तु समझौते के एक महत्वपूर्ण पक्ष यू यू पी ने कट्टरपंथी रुख अपना लिया है । इसका प्रमुख कारण संभवत: यह है कि शांति समझौते के क्रियान्वयन द्वारा यूनियनिस्टों को शीघ्र ही ऐसे सुधारों को निगलना पड़ता, जिससे उनकी विशेषाधिकारों वाली स्थिति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता । प्रस्तावित सुधारों में उत्तरी आयरलैण्ड व आयरलैण्ड में सहयोग, पुलिस में सुधार, कैथोलिक व प्रोटेस्टैंट के मध्य समानता स्थापित करने के उपायों को स्वीकृति व परासैन्य सैनिकों की शीघ्र रिहाई जैसे मुद्दे सम्मिलित हैं । निश्चित रूप से इससे उत्तरी आयरलैण्ड की स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता, जिससे संभवत: अल्स्टर यूनियनिस्ट बचना चाहते हों और इसकेलिए आइ आर ए के शस्त्र समर्पण मुद्दे को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं । यद्यपि समझौते के बाद के एक वर्ष का अनुभव आशा और निराशा का सम्मिश्रण रहा है, तथापि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शुभ शुक्रवार समझौते ने उत्तरी आयरलैण्ड समस्या के समाधान के लिए जो प्रक्रिया आरम्भ की है, उसका भविष्य शान्ति के पथ पर अग्रसर होने में ही निहित है ।

अध्ययन के निष्कर्ष

इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य यह समझना था कि कैसे और किन कारणों से एक अत्यन्त प्रभावी व शक्तिशाली गुरिल्ला समूह द्वारा एक अत्यंत प्रभावी लोकतांत्रिक राज्य के विरुद्ध जारी लम्बे व रक्तरंजित संघर्ष का समाधान संभव हुआ । उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौता, राजनयिक परामर्श द्वारा संघर्ष समाधान के क्षेत्र में

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए कई सैद्धांतिक व व्यावहारिक पाठ प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी स्थानीय संघर्ष को भी व्यापक विश्व से अलग कर शून्य में नहीं समझा जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आये परिवर्तन संघर्ष को प्रेरित करने वाले आंतरिक व बाह्य कारकों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। संघर्ष का अन्त सिर्फ इसके लम्बे समय तक चलने से हुआ या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्न ही है[5], किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि संघर्ष के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों के परिवर्तन का प्रभाव अवश्य पड़ा। 1960 के दशक की विभीषिका के दौरान उत्पन्न हुआ उत्तरी आयरलैण्ड संघर्ष 1920 और 1980 के दशकों में शीतयुद्ध से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाता रहा किन्तु 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व के अनेक भागों में जो शांति प्रक्रिया आरम्भ हुई (जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व में) उससे यह भी अछूता न रह सका।

इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि किसी भी शांति प्रक्रिया के सफल समझौते के रूप में परिणत होने के लिए यह आवश्यक है कि संघर्षरत सभी पक्ष राजनयिक परामर्श की प्रक्रिया में शामिल हों। ब्रिटिश सरकार की सिनफेन को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित करने की प्रतिबद्धता ने समझौते तक पहुंचने में अहम् भूमिका

----

5. देखें - एंथोनी मैकिनटाइरे, "मार्डन आयरिश रिपब्लिकनीम : द प्रोडक्ट आफ ब्रिटिश स्टेट स्ट्रेटेजी," आयरिश पालिटकल स्टडीज, अंक 10, 1995 पृ0 97-121

निभायी । सभी दलों के परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि समझौते के द्वारा सभी दलों को संतुष्ट किया जा सके । उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौते में सभी पक्षों को संतुष्ट करने के प्रावधान स्पष्ट हैं और शांति समझौते के एक साल के क्रियान्वयन में यू यू पी के द्वारा उत्पन्न किया गया व्यवधान यह इंगित करता है कि समझौते की शर्तों के अनुसार हो रहा परिवर्तन यू यू पी के संकीर्ण हितों के अनुकूल नहीं है ।

इस अध्ययन का तीसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि संघर्षों की प्रकृति और उनके समाधान की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि आज जो `उग्रवादी` और `आतंकवादी` हैं, वही कल शांति स्थापित करने वाला भी हो सकता है । विश्व के अन्य भागों में भी इसबात के उदाहरण मिलते हैं , चाहे वो अलसाल्वाडोर में शांति प्रक्रिया की पहल करने वाले अलफ्रेडो क्रिस्टानी रहे हों या फिर मध्य पूर्व में फिलस्तीन मुक्ति मोर्चा के प्रमुख यासिर अराफात । उत्तरी आयरलैण्ड के संदर्भ में बुजुर्ग आई आर ए नेता `जो कहिल` और प्रोटेस्टैंट परासैन्य के `गस्टी स्पेन्स` का शांति के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा ।

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में इस बात की भी विवेचना महत्वपूर्ण है कि शांति स्थापित करने में नीतियों और नीति निर्माताओं का क्या योगदान होता है । उत्तरी आयरलैण्ड के संदर्भ में यह स्पष्ट परिलक्षित है कि यद्यपि शांति के लिए प्रयास 1980 के दशक में ही आरम्भ

हो गये थे किन्तु इसके समझौते के रूप तक पहुंचने में अनेक वर्ष लगे । आई आर ए के युद्ध विराम की प्रथम उद्घोषणा 1994 में होने के बाद भी समझौते में चार वर्ष लगे । आखिर इतना समय क्यों व्यतीत हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राजनीति और राजनेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और अन्तत: तीन देशों में (आयरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका) आयी नयी सरकारों के बाद ही समझौता संभव हुआ । इसका यह तात्पर्य नहीं कि इन्हीं सरकारों के कारण अथवा राजनेताओं की वजह से ही समझौता संभव हुआ अपितु आशय यह है कि यदि राजनैतिक इच्छा हो तो संघर्षों का समाधान किया जा सकता है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन बिन्दु मध्यस्थ की भूमिका के विषय में रहा । समझौते के दौरान अमरीका द्वारा की गयी मध्यस्थता ने यह प्रमाणित किया कि राजनयिक परामर्श के दौरान शक्तिशाली मध्यस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जहां कहीं संवादहीनता की स्थिति हो अथवा आपसी हितों की टकराहट का प्रश्न हो, वहां मध्यस्थ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । समझौते के क्रियान्वयन के पक्ष को देखकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राजनयिक परामर्श के दौरान जहां मध्यस्थ की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहीं समझौते के क्रियान्वयन में यह बहुत प्रभावी नहीं है और अंतत: समझौते का सफल क्रियान्वयन संघर्षरत पक्षों की इच्छा पर ही निर्भर करता है ।

अन्तत: उत्तरी आयरलैण्ड शांति समझौता इस बात को अन्तत: प्रमाणित करता है कि यद्यपि सभी संघर्ष एक न एक दिन समाप्त होते

हैं , परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि संघर्ष के मूल कारणों का समाधान एकबारगी हो जाय । शांति स्थापित करना जहां अपने आप में महत्व-पूर्ण है, वहीं एक स्थिर समाज का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है । शांति के लिए किया गया समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

अन्त में अलस्टर के महानतम कवि लुईस मैकनीश की कलम से निकली शांति की आशा करती यह पंक्तियां आज भी प्रासंगिक लगती हैं ।

जो हो सकता है हासिल
देखें सपने उसके ।
उन कठपुतलों से पिण्ड छुड़ाएं
जिनकी आखें निद्रा से बोझिल -
पूजें पावन उस मातृभूमि को
जहां रह सके भाव तथा विचार संतुलित ! +

--

+ इफ इट इज समथिंग फिजिकल, आब्टैनेबल,
लैट अस ड्रीम इट नाउ ।
एण्ड प्रे फार ए पोसिब्ल लैण्ड
नाट आफ स्लीप-वाकर्स, नाट आफ एंगरी पपेट्स,
बट वेअर बोथ हार्ट एण्ड ब्रेन कैन अण्डरस्टैण्ड ।

संदर्भ सूची

पुस्तकें

- अजार, एडवर्ड, द मैनेजमेंट आफ प्रोट्रेक्टेड सोशल कानफ्लिक्ट : थ्यौरी एण्ड केसस, अल्डरशाट : डर्टमाउथ, 1990
- एडम्स, गैरी, सेलेक्टेड राइटिंग्स, डिगले, ब्राउन, 1992
- फ्री आयरलैण्ड : ट्वार्ड्स ए लास्टिंग पीस, डिंगले : ब्रान्डन, 1995
- एडवर्ड्स डुडली, एन एटलस आफ आयरिश हिस्ट्री, लंदन, मैथ्युन, 1973
- एण्डरसन, बेंडिक्ट, इमेजिन्ड कम्युनिटिज : रिफ्लेक्शंस आन द औरिजन एण्ड स्प्रैड आफ नेशनलिज्म, लंदन, वर्सो, 1991
- इक्ले, फ्रेड एवरी वार मस्ट एंड, न्यूयार्क : कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997
- क्लेरी, कौनोर ओ, डियरिंग डिप्लोमेसी : क्लिंटन्स सीक्रेट सर्च फार पीस इन आयरलैण्ड, बौल्डर, 1997
- द ग्रीनींग आफ द व्हाइट हाउस, डबलिन : गिल एण्ड मैकमिलन, 1997
- कर्नि, रिचर्ड, पोस्टनेशनलिस्ट आयरलैण्ड - पालिटिक्स कल्चर, फिलास्फी, लंदन : राउटलेज, 1997

- कियर्नी ह्युज, द ब्रिटिश आइरल्स : ए हिस्ट्री आफ फोर नेशनस, कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1989

- कियांग डरमाट और माइकल एच. हाल्टजेल (संपा0) नार्दन आयरलैण्ड : द पालिटिक्स आफ रिकान्सीलिएशन, वाशिंगटन डी.सी., वुड्रो विल्सन सेन्टर, 1993

- कीटिंग, पैट्रिक (संपा0), यूरोपियन सिक्योरिटी : आयरलैण्ड्स च्वायस, डबलिन : इंस्टीट्युट आफ यूरोपीयन अफेयर्स, 1996

- कैश, जान डी., आइडेन्टीटी आइडियालाजी एण्ड कानफ्लिक्ट : द स्ट्रक्चर आफ पालिटिक्स इन नार्दन आयरलैण्ड, कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1996

- कानार वाल्कर, एथनोनेशनलिज्म, द क्वेस्ट फार अण्डरस्टैंडिंग, प्रिंसटन : प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस, 1994

- गिब्सन, पीटर, द ओरिजन आफ अलस्टर यूनियनिज्म : द फार्मेशन आफ पाप्युलर प्रोटेस्टेंट पालिटिक्स एण्ड आएडियालाजी इन नार्दन आयरलैण्ड, मैनचेस्टर : मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975

- चैलेन्ज एण्ड अपारच्युनिटिज एब्राड : व्हाइट पेपर आन फारेन पालिसी, डबलिन : विदेश मंत्रालय आयरलैण्ड, 1996

- जारमैन, नील व डोमिनिक ब्रायन, फ्राम रायट्स टू रायट्स : नेशनलिस्ट परेड्स इन द नार्थ आफ आयरलैण्ड, कोलारिन : सेन्टर फार द स्टडी आफ कौनफ्लिक्ट, 1998

- टिल्ली, चार्ल्स, कोअरशन, कैपिटल एण्ड युरोपीयन स्टेट्स, आक्सफोर्ड : बेसिल ब्लैकवेल, 1990

- ह्यून, सीमंस (संपा0), फैशट्स आफ द कानफ्लिक्ट इन नार्दन आयरलैण्ड, लंदन : मैकमिलन, 1995

- पोलेंट, राबर्ट, द मेकिंग आफ युरोप : कान्क्वेस्ट फालोनाइजेशन एण्ड कल्चरल चेंज : 950 - 1350, लंदन : पेंग्विन, 1994

- फुल्टन, जान, द ट्रेजिडी आफ बिलीफ : डिवीजन, पालिटिक्स एण्ड रिलीजन इन आयरलैण्ड, आक्सफोर्ड : क्लेरेन्डन, 1991

- फोनिक्स, ह्यान, नार्दन नेशनलिज्म : नेशनलिस्ट पालिटिक्स, पार्टीशंस एण्ड द कैथोलिक माइनारिटी इन नार्दन आयरलैण्ड 1890-1940, बेलफास्ट, अलस्टर हिस्टारिकल फाउंडेशन, 1974

- ब्यु, पाल व गोर्डन ग्लिसपी (संपा0), द नार्दन आयरलैण्ड पीस-प्रोसेस, 1993-1996, लंदन : शेरिफ, 1996

- बर्कोविच, जेकब, सोशल कानफ्लिक्टस एण्ड थर्ड पार्टीज : स्ट्रेटाजेस आफ कानफ्लिक्ट रिजोल्युशन, बोल्डर : वेस्ट व्यु प्रेस, 1984

- बर्टन, जान डब्युय, कानफ्लिक्ट रिजोल्यूशन एण्ड प्रिवेंशन, लंदन, मंकमिलन, 1990

- बारेन्ज, जानेथन, ए हिस्ट्री आफ अलस्टर, बेलफास्ट : ब्लैक स्टाफ, 1992

- बिशप, पी. व इ. मेली, द प्रोविजनल आइ आर ए, लंदन, हीनमैन, 1987

- बेल, जे. बोअर, आयरिश टैक्टिक्स एण्ड टारगेट्स, डबलिन, पूलबेग प्रेस, 1990

- , द आयरिश ट्रबुल्स : ए जेनरेशन आफ वायलेन्स, 1967-1992, डबलिन : गिल व मैकमिलन, 1993

- , बैक टू द फ्युचर : द प्रोटेस्टेंट्स एण्ड ए युनाइटेड आयरलैण्ड, डबलिन, पूलबेग प्रेस, 1996

- ब्रायन, ब्रेडन ओ. द लौंगवार : द आइ आर ए एण्ड शिनफेन : फ्राम आर्यंड स्ट्रगल टू पीस टाक्स, डबलिन : ओब्रायन प्रेस, 1993

- ब्रेडी, शीयरन व रैमण्ड गिलेस्पी (संपा0) नैटिव्स एण्ड न्युकमर्स : द मेकिंग आफ आयरिश कोलोनियल सोसायटी 1534 - 1641, डबलिन : आयरिश एकेडमी प्रेस, 1986

- मैली, एमाकीन व डेविड मैक्क्रिट्रिक, फास्ट फार पीस : द सीक्रेट स्टोरी बिहाइन्ड द आयरिश पीस प्रोसेस, लंदन, हीनमैन, 1996

- रुआन, जोसेफ और जेनिफर टाड, द डायानमिक्स आफ कानफ्लिक्ट इन नार्दन आयरलैण्ड : पावर कानफ्लिक्ट एंड इमेनसीपेशन, कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1996

- रोसेनवाम (संपा0), अगेंस्ट होमरूल : द केस फार दि युनियन, लंदन, फ्रेडरिक गर्नर, 1992

- रंगराजन, एल0 एन0, द लिमिटेशन आफ कानफ्लिक्ट : ए थ्योरी आफ बारगेनिंग एण्ड निगोशिएशन, लंदन : क्रूमहेल्म, 1985

- लिज्पहार्ट, अरेन्ड, डेमोक्रेसी इन प्लयुरल सोसाइटीज : ए कम्परेटिव एक्सप्लोरेशन, न्यु हैवेन : येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1977

- लेरी, ब्रेडन, ओ व जान मैक्गेरी, द पालिटिक्स आफ एटागोनिज्म : अन्डरस्टैन्डिंग नार्दन आयरलैण्ड, लंदन : एथोलन, 1993

- व्हाइट, जान, इन्टरप्रेटिंग नार्दन आयरलैण्ड, आक्सफोर्ड, क्लारडन प्रेस, 1990

- वोल्कन, वामिक एवं अन्य (संपा0), द शायको डानामिक्स आफ इन्टरनेशनल रिलेशनशिप्स : वाल्यूम 1 : कान्सेप्ट्स एण्ड थ्योरिज, लेक्सिंगटन, लेक्सिंगटन बुक्स, 1990

- वालेसटाइन, इमेनुअल, द माडर्न वर्ल्ड सिस्टम, 3 भाग, न्यू यार्क : एकेडामिक प्रेस, 1974, 1980, 1984

- स्मिथ, एम. एल. आर, फाइटिंग फार आयरलैण्ड : द मिलट्री स्ट्रैटजी आफ द आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट, लंदन, राउटलेज, 1995

- स्लोआन, जी. आर., द जिओपालिटिक्स आफ एंग्लो-आयरिश रिलेशन इन द टवैंटिएथ सेन्चुरी, लंदन : लीस्टर युनिवर्सिटी प्रेस, 1997

- हालेण्ड, जैक, द अमेरिकन कनेक्शन : यू एस गन्स, मनी एण्ड इन्फ्लुएंस इन नार्दन आयरलेण्ड, हार्मोन्ड्सवर्थ : पैंग्विन, 1988

- हिल्ल क्रिस्टोफर, रिफार्मेशन टू इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन, हार्मोन्ड्सवर्थ पैंग्विन, 1969

लेख

- अगेस्टम, केरन व क्रिस्टर जानसन, 'अनएंडिंग कानफ्लिक्ट : चैलेन्जज इन पोस्ट वार बारगेनिंग', मिलिनियम, भाग 26, अंक 3, 1997, पृ0 792-813

- अजार, एडवर्ड चुंग इन इव, 'मैनेजिंग प्रोट्रैक्टेड सोशल कानफ्लिक्ट इन द थर्ड वर्ल्ड : फैसिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट इन डिप्लोमेसी', मिलिनियम, भाग 15, नं0 3, पृ0 393-406

- अब्राहम, थामस : 'टू पीस मेकर्स', फ्रंटलाइन, 20 नवम्बर, 1998, पृ0 54-55

- , 'यस टू पीस', फ्रंट लाइन, 19 जून, 1998, पृ0 62-63

- , 'एनादर चांस फार पीस', फ्रंट लाइन, 8 मई, 1998, पृ0 51-53

- 'अल्टरनेटिव अलस्टर', द इकानमिस्ट, 19 सितम्बर, 1998, पृ0 70-71

- आवलिन फिक्नोउला नी., 'व्हेअर होप एण्ड हिस्ट्री राइम-प्रासपेक्ट्स फार पीस इन नार्दन आयरलैण्ड', जर्नल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स, भाग 50, अंक 1, पृ0 63-89

- 'इंटरनेशनल पनल आस्क्स ब्रिटेन टू इज टर्म्स आन आइ आर ए
  टाक्स', न्यूयार्क टाइम्स, 24 जनवरी, 1996

- इवान्स अरनेस्ट : 'द यू एस पीस इनीशिएटिव इन नार्दन आयर-
  लैण्ड : ए कम्परेटिव एनालासिस' - यूरोपियन
  सिक्योरिटी, भाग 7, अंक ?, 1998, पृ0 63-77

- एथोनी मैकइनटिरे, 'मार्डन आयरिश रिपब्लिकनशिप द प्रोडक्ट
  आफ ब्रिटिश स्टेट स्ट्रेटजीज', आयरिश पालिटिकल स्टीज,
  भाग 10, 1995, पृ0 97-121

- काक्स, माइकल, 'सिन्ड्रेला एट द बाल : एक्सप्लेनिंग द एन्ड आफ
  द वार इन नार्दन आयरलैण्ड', मिलेनियम, भाग 27,
  अंक 2, पृ0 325-342

- कोहेन, स्टीफन व हैरियट एरोनन, 'कानफ्लिक्ट रिजोल्युशन
  एस द अल्टरनेटिव टू टेरशिज्म', जर्नल आफ सोशल
  इश्युज, भाग 44, अंक 2, 1988, पृ0 175-189

- गैरेट फिटजगेराल्ड व पाल गिलेस्पी, 'आयरलैण्ड्स ब्रिटिश
  क्वेशचन', प्रीस्पैक्ट, भाग 12, 1996, पृ0 25-37

- गुथलिक, एड्रियन, 'द यूनाइटेड स्टेट्स आयरिश अमेरिकन्स एण्ड
  द नार्दन आयरलैण्ड पीस प्रोसेस', इंटरनेशनल अफेयर्स,
  भाग 72, अंक 3, 1996, पृ0 521-36

- ,'कम्पैरिटिव ली पीसफुल : द रोल ऑफ एमोलाजी
  इन नार्दन आयरलैण्ड्स पीस प्रोसेस', कैम्ब्रिज रिव्यू
  आफ इंटरनेशनल अफेयर्स, भाग 11, अंक 1, 1997,
  पृ0 28-45

- 'गो फारवर्ड ड्रीम्स', संपादकीय, न्युस्टेट्समैन, 10 अप्रैल, 1998, पृ0 4

- जोसेफ ह फैलान, 'आयरलैण्ड : टू स्टेट्स, टू नेशंस', वर्ल्ड अफैयर्स, भाग 1581, 1995, पृ0 68-72

- 'ट्रिम्बल टू टैक हार्ड लाइन', द हिन्दु, 4 अप्रैल 1999

- ड्युन, सम्स, 'नार्दन आयरलैण्ड : ए प्रामिसिंग आर पार्टशियन पीस', जर्नल आफ इंटरनेशनल अफैयर्स, भाग 52, अंक 2, 1999, पृ0 719-733

- 'डिसीजन डे', द इकानामेस्ट, 16 मई 1998, पृ0 64-65

- डेलान्टी गेराई, 'निगोशिएटिंग द पीस इन नार्दन आयरलैण्ड', जर्नल आफ पीस रिसर्च, भाग 32, अंक 3, 1995, पृ0 257-264

- 'न्यु लेबर ओल्ड स्टोरी', द इकानमिस्ट, 11 जुलाई, 1998, पृ0 62-63

- 'प्रिवेंटिंग डेडली कानफ्लिक्ट', फाइनल रिपोर्ट : कारनेजी कमीशन, आन प्रिवेंटिंग डेडली कानफ्लिक्ट, न्युयार्क, कारनेजी कारपोरेशन, 1997

- पाल आर्थर 'अमेरिकन इंटरवेंशन इन द एंग्लो-आयरिश पीस प्रोसेस : इंकमिंटलिस्ट आर इंटरफ्रेंस', कैम्ब्रिज रिव्यू आफ इंटरनेशनल स्टीज, भाग 11 , अंक 1, 1997, पृ0 46-62

- 'फ्राम फारवर्ड मार्च टू रिट्रीट', द इकानमिस्ट, 18 जुलाई, 1998, पृ0 55-56

- 'फ्राम प्रोसेस टू प्रोसेशन', द इकानमिस्ट, 18 अप्रैल, 1998, पृ0 15-18

- फिशर, रोनाल्ड जे., 'थर्ड पार्टी कन्सलटेशन एज ए मेथड आफ इंटरग्रुप कानफ्लिक्ट रिजोल्युशन : ए रिव्यु आफ स्टीज', जर्नल आफ कानफ्लिक्ट रिजोल्युशन, भाग 27, अंक 2, जून 1983, पृ0 301-334

- ब्लूमफील्ड, डेविड, 'टु अर्डस काम्पलिमेन्ट्रियटी इन कानफ्लिक्ट मैनेजमेंट : रिजोल्युशन एण्ड सेटलमेंट इन नार्दन आयरलैण्ड', जर्नल आफ पीस रिसर्च, भाग 32, अंक 2, 1995, पृ0 151-161

- मेकिंटाश्रे, एंथोनी, 'मार्डन आयरिश रिपब्लिकनिज्म : द प्रोडक्ट आफ ब्रिटिश स्टेट स्ट्रेटेजी', आयरिश पालिटिकल स्टीज, अंक 10, 1995, पृ0 97-121

- मोहान, एलिजाबेथ, 'ब्रिटिश आयरिश रिलेशन इन द कान्टेक्स्ट आफ द यूरोपियन यूनियन', रिव्यू आफ इंटरनेशनल स्टीज, भाग 35, अंक 3, 1993, पृ0 26-38

- 'यू एस लिंक्स विद ब्रिटेन वर्स्ट सिंस 1973', द टाइम्स, 16 अगस्त, 1996

- लिने, थामस, 'आयरलैण्ड, नार्दन आयरलैण्ड एण्ड 1992 : द बेरियर टू टेक्नोक्रेटिक एन्टीपार्टीशन', पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाग 18, विंटर, 1990, पृ0 417 - 437

- 'लाइफ आफ्टर डेथ इन आयरलैण्ड', सम्पादकीय, न्यु स्टेट्समैन, 16 जनवरी, 1998, पृ0 5

- लाल्यड, जान, 'आयरलैण्ड्स अनसर्टेन पीस', फॉरेन अफेयर्स, भाग 77, अंक 5, 1998, पृ0 109-122

- ,'नाउ डबलिन मस्ट डिसाइड', न्यू स्टेट्समैन, 4 फरवरी, 1997, पृ0 16-17
- ,'इनटू द वेरी लास्ट लेप', न्यू स्टेट्स मैन, 25 अप्रैल, 1997, पृ0 16-17
- 'अलस्टरस हार्ट स्टापिंग मोमेंट', न्यू स्टेट्समैन, 3 अप्रैल 1998, पृ0 10-12
- 'द वेट आफ हिस्ट्री हैंगिंग ओवर अलस्टर', न्यू स्टेट्समैन, 24 अप्रैल 1998, पृ0 14-15
- 'द वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट मिक्सचर', न्यू स्टेट्समैन, 21 अगस्त 1998, पृ0 8-9
- 'ट्रिम्बल प्रिपेअरस फार हिज फाइनल स्टैण्ड', न्यू स्टेट्समैन, 5 फरवरी 1999, पृ0 10-11
- 'वार, पीस एण्ड पालिटिक्स', संपादकीय, न्यू स्टेट्समैन, 17 अप्रैल 1998, पृ0 6
- स्मिथ एम एल आर, 'द इंटलैक्टअल इंटरन्मैंट आफ ए कानफ्लिक्ट : द फारगाटेन वार इन नार्दन आयरलैण्ड', इंटरनैशनल अफेयर्स, अंक 1, 1999 , पृ0 783-807
- सिनोट, रिचर्ड, 'आयरलैण्ड : चेन्जिंग गर्वन्मैंट्स, पार्टीज एण्ड वोर्टस', द वर्ल्ड टुडे, मई 1995, पृ0 89-93
- सिनॉट, रिचर्ड आर बी. व्हेलन,'कन्जरवेटिव्स, लिबरल्स एण्ड प्रागमैटिस्ट्स : डिसएग्रीगेटिंग द रिजल्ट आफ द प्री-एबार्शन रिफ्रेन्डम्स आफ नवम्बर 1992', इकानोमिक एण्ड सोशल रिव्यू, भाग 26, 1995